घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 135- बुधवार 18- मार्च 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

कांग्रेस ने ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी से निकाला

भुवनेश्वर,17 मार्च 2026। ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस पांच विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। ओडिशा में कांग्रेस ने रमेश जेना,दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकाला है। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल,दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 16 मार्च को 11 सीटों पर हुए चुनाव में 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। इससे पहले 10 राज्यों की 37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे।

बंगाल की सभी सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार घोषित,भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

कोलकाता,17 मार्च 2026। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार 52 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है,जिसमें युवा तथा अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि दार्जिलिंग क्षेत्र की तीन सीटों पर तृणमूल चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कालीघाट स्थित अपने आवास से 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, उन्हें पार्टी संगठन में अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि तृणमूल पहले से अधिक सीटें जीतेगी, क्योंकि पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच रहती है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को लाकर राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है और जनता इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से प्रतिद्वंद्विता की थी और शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। इस बार वहां से पवित्र कर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो आज ही भाजपा छोड़ कर टीएमसी में शामिल हुए हैं।

आयोग ने पंजाब के 26 आईएएस और 7 आईपीएस को सौंपी 5 राज्यों के चुनाव की कमान

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। केंद्र के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब से 26 वरिष्ठ आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों को बतौर जनरल और सुरक्षा आब्जर्वर नियुक्त किया है। इन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और 4 मई को नतीजे आने तक संबंधित राज्यों में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये अधिकारी नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना तक पूरे चुनावी घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। उन्हें अपने-अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में जिला डिप्टी कमिश्नरों और रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशों के तहत कार्य करना होगा। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तैनात अधिकारियों में राहुल तिवाड़ी, गुरकीरत किरपाल और प्रियंक भारती जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जबकि आईपीएस अधिकारियों में कौस्तुभ शर्मा प्रमुख नाम हैं। खास बात यह है कि छह महिला अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई है। इनमें अपनीत रियात और दीप्ति उप्पल को केरल, सेना अग्रवाल और सोनाली गिरी को पश्चिम बंगाल और अलका मीना को असम में तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई है,जहां अमित ढाका,अरविंद कुमार एमके,हरप्रीत सिंह सूदन,अजीत बालाजी जोशी,कुलवंत सिंह,परमिंदरपाल सिंह,रामवीर, शौकत अहमद पारे,सैयद सहरिश असगर और वरुण रुजम समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

बच्चों को पोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना जरूरी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति मुर्मु ने मंगलवार को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पांच अरब भोजन परोसने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। पीएम पोषण के तहत चल रहा स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अभिभावकों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित हुआ है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना से बच्चों के नामांकन,उपस्थिति और स्कूल में टिके रहने की दर में वृद्धि हुई है, साथ ही उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन 'समग्र शिक्षा अभियान' के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है,जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा...पोस्टर और एआई से बनीं तस्वीरें न दिखाएं

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। लोकसभा में मंगलवार को पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के एक सांसद हैं। ये आठ सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका समर्थन किया। धर्मेंद यादव ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसका ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा,'प्लेकार्ट और एआई से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें।' सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा,'स्पीकर ने कुछ निर्देश दिए हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी सदन की मर्यादा और अनुशासन का जिक्र किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाएगा। '

शिवराज चौहान ने कहा...कांग्रेस ने सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की...

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा,'कुछ कांग्रेस शासित राज्यों को योजनाओं में 'पीएम' नाम पसंद नहीं है, इसलिए 1,93,000 घरों को मंजूरी नहीं दी गई।'उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत देश के गरीब परिवारों को इलाज देता है। कांग्रेस ने कभी गरीबी खत्म नहीं की। आपने किसकी गरीबी दूर की,आपने सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की। उन्होंने कहा,'पीएम आवास योजना के सर्वे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पीएम मोदी ने दोबारा सर्वे कराने को कहा है,ताकि यह पता चल सके कि एक घर में कितने लोग रहेंगे।'

अश्विनी वैष्णव बोले... मोदी सरकार के 10 साल में रेलवे की आर्थिक हालत सुधरी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान रेलवे की आय और निवेश दोनों बढ़े हैं और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी तेजी से काम हुआ है।

सरकार ने लोकसभा से 'जन विश्वास संशोधन विधेयक' को वापस लिया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा से जन विश्वास विधेयक को वापस ले लिया। लोकसभा की चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद इस विधेयक को फिर से पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को और बढ़ावा देने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सदन की अनुमति लेने के बाद प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025' को वापस ले लिया। इससे पहले गोयल ने लोकसभा में 'जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025' को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक छोटे व्यावसायिक अपराधों को अपराधमुक्त करने और व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए 2025 में पेश किया गया था, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। इस बिल का उद्देश्य 'जीवन जीने में आसानी' (इज ऑफ लिविंग) और 'व्यापार करने में आसानी' (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए विश्वास-आधारित शासन को और अधिक सुदृढ़ करना है।

वित मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं... मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा की कमी नहीं

वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पूरक बजट मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि वेस्ट एशिया में संकट के बावजूद भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सरकार एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। घरेलू एलपीजी उत्पादन में कम से कम 25% की बढ़ोतरी हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सप्लाई व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

क्रॉस वोटिंग पर रार...हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पद छोड़ा,हुड्डा बोले-सब पता है...

चंडीगढ़,17 मार्च 2026। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रामकिशन विधायक शैली चौधरी के पति हैं। सोशल मीडिया पर शैली चौधरी के क्रास मतदान करने की चर्चा है। हालांकि अभी कांग्रेस की ओर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हाई कमान को उनके नाम बता दिए गए हैं। 2 से 3 दिन में सभी नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। राम किशन गुर्जर ने कहा कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोट नहीं किया बल्कि उनको बदनाम करने की नीयत से उनका नाम उछाला जा रहा है इस लिए विरोध स्वरूप मैं पार्टी पद से इस्तीफा देता हूं। वहीं बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि मेरा दिल,दिमाग और आत्मा दुखी है। कांग्रेस में भ्रष्ट लोगों की कदर है। कांग्रेस में रहने पर वत्स ने कहा कि वक्त बताएगा। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संख्या के अनुसार राज्यसभा चुनाव में दो सीटों के लिए 1-1 सीट बीजेपी और कांग्रेस को मिलनी तय थी लेकिन बीजेपी ने अपने एक पदाधिकारी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। हमने जब सदन में मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने हंगामा कर दिया।

राज्यसभा चुनाव 2026...एनडीए का दबदबा 37 में से 22 सीटों पर जमाया कब्जा

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावी समर के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की चुनावी रणनीति के आगे विपक्ष की तमाम कोशिशें बौनी साबित हुईं। बिहार, हरियाणा और ओडिशा की 11 सीटों पर सोमवार को हुए मतदान में एनडीए ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष के खाते में महज 2 सीटें आईं। बिहार में जहाँ आरजेडी और ओवैसी का समीकरण विफल रहा,वहीं ओडिशा में कांग्रेस और बीजेडी का साथ भी कोई कमाल नहीं दिखा सका। कुल 37 सीटों के अंतिम आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए को 22 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्ष 15 सीटों पर सिमट गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 37 सीटों में से 26 सदस्यों का निर्वाचन पहले ही निर्विरोध हो चुका था,जिनमें सत्तापक्ष और विपक्ष के पास 13-13 सीटें थीं। सोमवार के नतीजों ने एनडीए के पक्ष में पलड़ा पूरी तरह भारी हो गया। एनडीए की 22 सीटों में से भाजपा ने 13,जेडीयू ने 2, और अन्य सहयोगियों जैसे शिवसेना (शिंदे),एनसीपी (अजित पवार),पीएमके और एआईएडीएमके ने शेष सीटें जीती हैं। विपक्ष की 15 सीटों में कांग्रेस को 6,टीएमसी को 4 और डीएमके को 3 सीटें मिली हैं। राज्यवार नतीजों का विश्लेषण करें तो महाराष्ट्र की 7 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिली हैं। बिहार की 5 सीटों पर जेडीयू ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखीं,जबकि भाजपा को 2 सीटों का लाभ हुआ और आरजेडी को अपनी दोनों सीटें गंवानी पड़ीं।

ओडिशा में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत दिलाने में सफलता पाई। हरियाणा में मुकाबला बराबरी का रहा जहाँ भाजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट मिली।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु की 6 सीटों पर एआईएडीएमके और पीएमके अपनी साख बचाने में सफल रहे,जबकि तेलंगाना की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना किला सुरक्षित रखते हुए 4 सीटें जीतीं।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी

समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी,24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक

गांधीनगर,17 मार्च 2026। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट पेश की है। यूसीसी से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में ही की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है,जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। अगर यह बिल पास हो जाता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

महिलाओं के समान अधिकारों को प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर लिखा- गुजरात में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह,तलाक,संपत्ति में उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचा लागू करने का सुझाव दिया गया है। खास तौर पर महिलाओं के समान अधिकार और उनकी सुरक्षा को इस ड्राफ्ट में प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, रिपोर्ट तैयार करते समय गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं रंजना प्रकाश देसाई

पांच सदस्यीय इस समिति का गठन 4 फरवरी 2025 को किया गया था,जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। वे 13 सितम्बर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय में जज रहीं। जस्टिस रंजना देसाई जम्मू-कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देसाई सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जज भी रह चुकी हैं।

किसी भी उम्र का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व अवकाश,अभी उम्र 3 महीने से कम होना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सोशल सिक्योरिटी कोड,2020 से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया। हमसानंदिनी नंदूरी ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि उम्र के आधार पर छुट्टी देना गलत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पितृत्व अवकाश (पिता की छुट्टी) को भी कानून में शामिल करे। कोर्ट ने कहा कि इसकी अवधि माता-पिता और बच्चे की जरूरतों के अनुसार तय होनी चाहिए।

कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ को पेरावूर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं,विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन को पारावूर से पार्टी ने फिर टिकट दिया है, वह यहीं से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा रमेश चेन्निथला को हरिपद से,रम्या हरिदास को चिरयिनकीझु से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन को वट्टीयूरकाउ से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन को पुथुपल्ली से टिकट दिया गया है। वह वर्तमान में यहां से विधायक हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने मंगलवार को ही केरल के लिए इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई थी। मंगलवार को ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक हुई थी,जिसमें केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। इसके बाद अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे,पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी,संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल,प्रदेश प्रभारी दीपा दासमुंशी और कई अन्य नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने कहा,'पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कई नामों को मंजूरी दे दी है।

राहुल गांधी के खिलाफ 204 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स-सैन्य अधिकारियों का लिखा लेटर

संसद परिसर में आचरण नियमों के खिलाफ,देश से माफी मांगें

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। 204 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी,आईपीएस,आईएएस और वकीलों ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखकर देश से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने लिखा कि 12 मार्च को संसद परिसर में किया गया विरोध संसदीय नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ था।

ओपन लेटर में कहा गया कि संसद परिसर में प्रदर्शन या विरोध न करने को लेकर स्पीकर की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध किया। लेटर में आगे कहा कि राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट लेते हुए विरोध करते दिखाई दिए। यह संसदीय अधिकार और संसद की मर्यादा की अनदेखी है। संसद की सीढ़ियां राजनीतिक प्रदर्शन का मंच नहीं हैं। दरअसल,12 मार्च को विपक्ष ने एलपीजी संकट को लेकर सकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ संसद की सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दिए। वे वहां चाय और बिस्कुट लेते हुए विरोध कर रहे थे।

संसद परिसर के हर हिस्से में मर्यादा जरूरी : लेटर में कहा गया कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उसकी गरिमा हर समय बनी रहनी चाहिए। संसदीय परंपराओं के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा कक्ष ही नहीं,बल्कि संसद परिसर की सीढ़ियां,गलियारे और लॉबी भी उसी संस्था का हिस्सा हैं। इसलिए वहां भी सांसदों का आचरण उसी मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। लेटर में कहा गया कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक चर्चा के स्तर को गिराती हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं।

लेटर पर 204 लोगों के सिग्नेचर : यह ओपन लेटर जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ने जारी किया है। लेटर पर 204 लोगों ने साइन किए हैं। इनमें 116 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और 84 पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। इसके अलावा चार पूर्व राजदूत और चार सीनियर वकील भी सिग्नेचर करना वालों में शामिल हैं। लेटर में राहुल गांधी से अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करने और देश से माफी मांगने को कहा गया है।

संपादकीय

जन्मदात्री की रक्षा

हालांकि,पंजाब में पिछले दिनों सामने आए मातृ स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े कुछ हद तक उम्मीद जरूर जगाते हैं,लेकिन उन्हें संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। राज्य में बच्चे को जन्म देने के दौरान मातृ मृत्यु दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जो निश्चित रूप से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माताओं की सेहत की सुरक्षा करने में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता में क्रमबद्ध सुधार का ही संकेत देती है। लेकिन,इस मामूली गिरावट के बावजूद एक गंभीर चिंता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि प्रगति अभी भी धीमी व असमान गति वाली है। दरअसल,मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों के रूप में मापी जाती है। जिसे व्यापक अर्थों में किसी भी समाज की स्वास्थ्य सेवा की क्षमता तथा समाज में लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण सूचक भी माना जाता है। इस तरह मातृ मृत्यु दर में आई मामूली गिरावट भी प्रसव पूर्व गर्भवती स्त्री की देखभाल,संस्थागत स्तर पर प्रसव कराने और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की स्थिति में सुधार को ही दर्शाती है। इसके बावजूद अभी पंजाब में मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की काफी गुंजाइश है। विशेष रूप से तब जब कि कई जिलों में मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां जरूरी हो जाता है कि पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाए। हालांकि,पहले इस दिशा में आशातीत प्रगति दर्ज की गई थी। लेकिन अब हरियाणा की मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर के नवीनतम मूल्यांकन चक्र में स्थिति लगभग अपरिवर्तित ही नजर आती है। निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखी जा रही यह स्थिरता सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में एक आम चुनौती को ही उजागर करती है। निर्विवाद रूप से प्रारंभिक स्तर पर किए गए सुधार अक्सर त्वरित लाभ देते हैं,लेकिन जरूरी है कि इस दिशा में प्रगति को अनवरत बनाया रखा जाए। निस्संदेह,इस प्रगति के लिये निरंतर गहन संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत होती है। वास्तव में मातृ स्वास्थ्य रक्षा के लिये कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में केवल अस्पतालों और योजनाओं में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं होता है। बल्कि गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल,समय रहते रेफरल और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निरंतर निगरानी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल,पंजाब में स्वास्थ्य संबंधी ऑडिट से पहले ही प्रणालीगत खामियों की ओर संकेत मिला है। जैसा कि निदान में देरी, प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी जटिलताओं का खराब प्रबंधन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच कमजोर समन्वय का होना भी है। निस्संदेह,इन कमियों को दूर करने के लिये जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों से रेफरल नेटवर्क में यथाशीघ्र सुधार करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है।

भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करने का संकल्प लिया है। यदि पंजाब और हरियाणा को इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उन्हें अपने प्रयासों में योजनाबद्ध ढंग से तेजी लानी होगी। इसमें दो राय नहीं कि मातृ मृत्यु दर महज चिकित्सा आंकड़े नहीं है। ये वो रोकी जा सकने वाली त्रासदी है, जो कई परिवारों और समुदायों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। निर्विवाद रूप से इस दिशा में जहां शासन की ओर से सजगता व सतर्कता की आवश्यकता होती है,वहीं चिकित्सा तंत्र से इस दिशा में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमारे समाज में आमतौर पर श्रमिक व वंचित तबका ही सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, जो महंगे अस्पतालों में अपनों का इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है। वे वंश वृद्धि और मातृ रक्षा की आस में सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। निस्संदेह,पर्याप्त सुविधा का अभाव व समय पर उपचार न मिलने से होने वाली हानि व्यवस्था पर भरोसे को कम ही करती है।

हवामहल

डॉ. सुरेश कुमार मिश्र

रामपुरिया गांव के स्वघोषित चाणक्य 'झपटल सिंह' का मानना था कि जनता उस मासूम बच्चे की तरह है जिसे प्लास्टिक का झुनझुना थमाकर उसकी असली वसीयत पर अंगूठा लगवाया जा सकता है। इस बार उन्होंने प्रधानी के चुनाव में किसी सड़क या नाली का वादा नहीं किया,बल्कि 'शुद्ध हवा' का टेंडर पेश कर दिया। झपटल सिंह ने गांव के प्राइमरी स्कूल की छत पर तीन पुराने लोहे के पंखे लगवाए और उन्हें 'स्वच्छ वायु संयंत्र' घोषित कर दिया। उनका तर्क था कि आने वाले समय में सांस लेना भी एक विलासिता होगी, और जो उन्हें वोट देगा,उसे 'प्रीमियम ऑक्सीजन' का कोटा मुफ्त मिलेगा। गांव के लोग, जो अब तक नीम और बरगद की मुफ्त हवा फांक रहे थे,अचानक इस 'विदेशी तकनीक' के मोहपाश में फंस गए। झपटल सिंह की बातों में इतना आकर्षण था कि गांव के गदहे भी अपनी रेकन छोड़कर उनके चुनावी भाषण सुनने के लिए कतारबद्ध खड़े हो जाते थे। प्रचार के अंतिम दिन झपटल सिंह ने गांव के मैदान में एक विशाल गुब्बारा फुलाया और उसे 'विकास का पावरहाउस' नाम दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस गुब्बारे के भीतर दिल्ली और मुंबई की 'पॉश' कॉलोनियों की हवा भरी है, जिसे सूंघते ही आदमी की बुद्धि आइंस्टीन जैसी हो जाएगी और उसे गरीबी का अहसास होना बंद हो जाएगा। विपक्षी उम्मीदवार 'गपोड़ी लाल' ने शोर मचाया कि यह तो केवल खाली हवा है, लेकिन झपटल सिंह ने पलटवार किया कि गपोड़ी लाल को हवा की 'क्वालिटी' की समझ नहीं है क्योंकि उनकी नाक में तो हमेशा गोबर की गंध बसी रहती है। देखते ही देखते,पूरा रामपुरिया गांव उस गुब्बारे के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। लोगों को लगने लगा कि अब बिना पंखे के भी उनकी किस्मत की खिड़कियां खुल जाएंगी और वे बिना कुछ किए ही 'स्मार्ट नागरिक' की श्रेणी में आ जाएंगे।

मतदान के अगले दिन जब झपटल सिंह की जीत का डंका बजा,तो जनता गुब्बारे के पास 'स्मार्ट हवा' लेने के लिए उमड़ पड़ी। झपटल सिंह ने एक बड़ी सी सुई निकाली और बड़े गर्व के साथ गुब्बारे में चुभो दी। एक ज़ोरदार 'फटाक' की आवाज़ हुई और गुब्बारा पिचक कर ज़मीन पर गिर गया। जनता के चेहरे पर हवा का एक झोंका तक नहीं लगा। लोग हक्के-बक्के रह गए और झपटल सिंह की ओर देखने लगे। झपटल सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले– 'भाइयों,वह हवा इतनी बारीक और हाई-टेक थी कि उसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके पास 'प्रधान' जैसा विजन हो! बाकी आप लोग तो साधारण फेफड़े वाले हैं, आपको तो बस मुफ्त की धूल फांकने की आदत है।' जनता एक-दूसरे का मुंह ताकती रह गई और झपटल सिंह अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर 'वायु प्रदूषण नियंत्रण' का सरकारी फंड डकारने के लिए शहर की ओर उड़नछू हो गए।

योगी से नाराज ब्राह्मण क्या बदल सकते हैं सियासी पाला

दिसंबर 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान जब भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में बैठक की तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तुरंत सख्त चेतावनी दे दी। कहा गया कि जाति आधारित बैठक राजनीति पार्टी को मंजूर नहीं। लेकिन ठीक उसी साल अगस्त में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई जिसमें चालीस से ज्यादा नेता शामिल थे। वह बैठक पांच सितारा होटल में हुई और उसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया। लोध और कुर्मी विधायकों की बैठक भी हुई लेकिन उन पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई चेतावनी नहीं मिली। सपा और कांग्रेस ने इस दोहरे मानदंड पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा में ब्राह्मण विधायक एक जगह जुट भी नहीं सकते और न ही अपनी बात रख सकते हैं...

अजय कुमार,
लखनऊ (उ. प्र.)

उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी रंग लगातार चटक होता जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए सभी हथकंडे अपनाये और हर छोटी-बड़ी घटना,हर बयान और हर फैसला अब चुनावी नजरिये से देखा जा रहा है कि इससे वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। फिलहाल यादव बिरादरी और मुसलमान काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं,लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री से सपा को नुकसान भी हो सकता है। ठीक इसी तरह ब्राह्मण समुदाय जो हमेशा से भाजपा का मजबूत वोट बैंक रहा है,उसमें योगी सरकार के प्रति आक्रोश उबल रहा है। जिसमें हाल ही में एसआई की परीक्षा में ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित सवाल ने ब्राह्मणों की नाराजगी को और बढ़ाने में आग में घी डालने का काम किया है। अब यह सवाल सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसने योगी सरकार के प्रति ब्राह्मणों के गुस्सा को और भी बढ़ा दिया है । राज्य पुलिस भर्ती की दरोगा परीक्षा में पूछा गया वह सवाल अब पूरे समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रतीक बन गया है। सवाल था अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है और उसके विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल कर दिया गया। एक सामान्य परीक्षा का सवाल जिसका मकसद सिर्फ ज्ञान जांचना था वह अब जाति विशेष को अवसरवादी बताने का हथियार बन गया। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तुरंत इसकी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सवाल से किसी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कहा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके दोस्तों को पकड़ने के लिए जांच कमेटी भी बना दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भर्ती बोर्डों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी जाति पंथ या संप्रदाय की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बार-बार गलती करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ क्षमा याचना और निर्देशों से काम चल जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज की नाराजगी अब एक-दो घटनाओं तक नहीं रही। यह एक सिलसिला बन चुका है जो पिछले कई महीनों से लगातार जारी है।

यह ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर सवाल था जो आज भी गूंज रहा है।फिर आया माघ मेला का विवाद। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोका। धक्का-मुक्की हुई। शंकराचार्य के समर्थक बटुक ब्राह्मणों की चोटियां खींचने के आरोप पुलिस पर लगे। मामला इतना बढ़ा कि शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और बिना स्नान किए लौट गए। सपा और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। बृजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर सौ बटुकों को सम्मानित किया लेकिन क्या यह कदम पर्याप्त था। समाज अभी भी कह रहा है कि प्रशासन ने शंकराचार्य के साथ जो रवैया अपनाया वह अपमानजनक था। फिर आई फिल्म घूसखोर पंडित। नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी अभिनीत इस फिल्म का टीजर फरवरी 2026 में जारी हुआ। पुलिस अधिकारी को पंडित कहकर संबोधित किया गया। ब्राह्मण संगठनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किए। यूपी में पोस्टर जलाए गए। सड़कों पर प्रदर्शन हुए। मामले ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने फिल्म रिलीज से पहले नाम बदलने का आदेश दिया और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया। निर्माता नीरज पांडे को शीर्षक बदलना पड़ा। ब्राह्मण समाज ने इसे साजिश बताया कि जानबूझकर एक समुदाय को भ्रष्ट और घूसखोर करार दिया जा रहा है। फिल्म का नया नाम अभी तक तय नहीं हुआ लेकिन समाज के दिल में जो चोट लगी वह अभी भी ताजी है।यूजीसी के नए नियमों ने भी सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों को नाराज किया। दलित और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नियमों को ब्राह्मणों ने अपने खिलाफ देखा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माघ मेले में शंकराचार्य शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार और यूजीसी नियमों को वजह बताया। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि नियम सामान्य वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और सामाजिक बंटवारा बढ़ा सकते हैं। केंद्र को नए नियम बनाने के लिए कहा गया। लेकिन इस दौरान ब्राह्मण सड़कों पर उतरे सोशल मीडिया पर विरोध हुआ। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक आईं और हर बार सरकार को सफाई देनी पड़ी। हर बार डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन ब्राह्मण समाज पूछ रहा है कि क्यों बार-बार उसकी भावनाओं की अनदेखी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या दस प्रतिशत से ज्यादा है। 2017 के बाद से भाजपा को इनका 85 से 90 प्रतिशत वोट मिलता रहा है। यह परंपरागत

वोट बैंक है जो पार्टी की रीढ़ रहा है। लेकिन 2017 के बाद ब्राह्मणों की शिकायत लगातार बढ़ी है। उन्हें पार्टी और सरकार में उचित सम्मान नहीं मिल रहा। उनकी बात नहीं सुनी जा रही। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक में कर्तव्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात कही थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद खामोशी छा गई। अब सपा इस नाराजगी को अपना हथियार बना रही है। उसके ब्राह्मण नेता लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं। ब्राह्मण समाज के संगठन खुलकर कह रहे हैं कि भाजपा ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है लेकिन सम्मान नहीं दिया। ठाकुर कुर्मी लोध जैसे अन्य समुदायों की बैठकें बिना किसी रोक टोक के हो जाती हैं लेकिन ब्राह्मणों की बैठक पर तुरंत नोटिस। परीक्षा का सवाल पंडित को अवसरवादी बताता है। फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रखा जाता है। माघ मेले में बटुकों के साथ बदसलूकी। यूजीसी नियम सामान्य वर्ग को निशाना बनाते हैं। ये सारे मुद्दे एक साथ जुड़कर ब्राह्मणों को यह अहसास दिला रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है।2027 के चुनाव में अगर ब्राह्मण वोट में सिर्फ पांच प्रतिशत भी कमी आई तो भाजपा के कई सीटों पर असर पड़ सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में हैं। पार्टी के अंदर भी ब्राह्मण नेता चुपचाप असंतोष जता रहे हैं। लेकिन ऊपर से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा। सरकार को अब सिर्फ निर्देश जारी करने से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे। ब्राह्मण संगठनों से संवाद बढ़ाना होगा। परीक्षा बोर्डों में सख्त निगरानी करनी होगी। फिल्म और मीडिया में जाति आधारित अपमान को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मजबूत करने होंगे। यूजीसी जैसे मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखानी होगी। ब्राह्मण समाज सदियों से ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का संरक्षक रहा है। अवसरवादी या घूसखोर जैसे शब्दों से उसे जोड़ा जाना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी। योगी सरकार ने विकास और कानून व्यवस्था पर जोर दिया है लेकिन अगर सामाजिक संतुलन बिगड़ गया तो पूरा प्रयास प्रभावित हो सकता है। ब्राह्मण नाराजगी अब सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं रह गया है। यह सियासी गणित का हिस्सा बन चुका है। अगर सरकार ने समय रहते इसे समझा और ठीक किया तो 2027 में यह खतरा टल सकता है। वरना यह बादल और घने होते जाएंगे और चुनावी मैदान में भारी पड़ सकते हैं। ब्राह्मण समाज की आवाज अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि चेतावनी का अलार्म बन चुकी है। सरकार को इसे अनसुना नहीं करना चाहिए।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का धर्मस्वातंर्त्य विधेयक समर्थन हिंदुत्व की घर वापसी का संकेत

संजय सक्सेना
लखनऊ

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उस पुरानी विचारधारा की छाप उभर रही है जिसने सदियों से इस भूमि को अपनी पहचान दी है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में पेश हुए धर्मस्वातंर्त्य विधेयक को पूर्ण समर्थन देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जबरदस्ती या लालच के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ उनका रुख अडिग है। यह समर्थन महज एक विधेयक की मंजूरी तक सीमित नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। पांच साल पहले जब उन्होंने सत्ता की खातिर दशकों पुरानी सहयोगी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब कई लोगों ने इसे उनकी विचारधारा से समझौता मान लिया था। लेकिन अब जब विधेयक पास हो चुका है और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि धर्म स्वातंर्त्य तो हर किसी को होना चाहिए पर फरेब या दबाव से धर्म बदलवाने का विरोध करेंगे तब लगता है कि वे अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं।

यह बदलाव अचानक नहीं आया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में कई ऐसे फैसले आए जिनसे उनके पारंपरिक हिंदू मतदाता नाराज हो गए। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या सावरकर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ तालमेल तो उद्धव की चुप्पी ने उनके कैडर में असमंजस पैदा कर दिया। उस समय मुस्लिम वोटरों की स्वीकार्यता बढ़ी जरूर लेकिन शिवसेना की मूल हिंदुत्ववादी छवि धुंधली पड़ती गई। फिर 2022 में पार्टी में फूट पड़ी जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहुसंख्यक विधायक अलग हो गए और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) तब विपक्ष में चली गई और महाविकास आघाड़ी के सहारे टिकी रही। लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया। पार्टी दो फाड़ होने के बावजूद चुनावी मैदान में बुरी तरह हार गई और मुस्लिम वोटों के भरोसे पुरानी जमीन बचाने का सपना चूर-चूर हो गया। अब अस्तित्व का संकट सामने है तो उद्धव को फिर से बाल ठाकरे की उस विचारधारा की याद आई है जिस पर शिवसेना की नींव पड़ी थी। धर्मस्वातंर्त्य विधेयक महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में अवैध धर्मांतरण पर सख्त लगाम लगाने का प्रयास करता है। विधेयक में जबरदस्ती लालच धोखा भ्रम प्रलोभन या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। नाबालिगों के मामले में तो प्रावधान और भी सख्त हैं। अगर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया गया तो वह शादी भी रद्द मानी जाएगी और बच्चों का धर्म माता-पिता के मूल धर्म के आधार पर तय होगा। कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहे तो उसे कम से कम साठ दिन पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी। पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है और एफआईआर किसी भी रिश्तेदार माता-पिता भाई-बहन या खून के रिश्तेदार द्वारा दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सबूत का बोझ आरोपी पर है उसे साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध था। सजा भी कड़ी है सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर पांच लाख तक का जुर्माना और दोबारा अपराध पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक महज कानून नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बचाने का एक प्रयास है। उद्धव ठाकरे का इस विधेयक को समर्थन देना महाराष्ट्र की राजनीति में एक दुर्लभ एकता का दृश्य प्रस्तुत करता है। महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को असंवैधानिक और एकपक्षीय बताया है लेकिन उद्धव ठाकरे ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर धर्म को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पर जबरदस्ती या लालच से धर्म बदलवाना गलत है। यह रुख उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि अवैध गतिविधियों को रोकने का माध्यम है। विधेयक पास होने के बाद अब विधान परिषद में चर्चा होगी और अगर वहां भी यह पारित हो गया तो महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां ऐसे कानून पहले से लागू हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में पहले ही सख्त प्रावधान हैं और इनके अनुभव से महाराष्ट्र सरकार ने भी सबक लिया है। यह समर्थन उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी को भी उजागर करता है। पिछले चुनावों में हार के बाद उनकी पार्टी को अपनी मूल पहचान वापस हासिल करने की जरूरत है। हिंदुत्व के बिना शिवसेना की कल्पना मुश्किल है और उद्धव जानते हैं कि मुस्लिम वोटों पर अकेले भरोसा करके वे अपनी पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को नहीं लौटा सकते। इसलिए यह घर वापसी उन्हें अपनी खोई हुई साख बचाने का मौका दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समर्थन केवल चुनावी रणनीति है या वास्तविक विचारधारा का पुनरागमन। जब वक्फ संशोधन विधेयक की बात आई तो उद्धव की पार्टी ने इसका विरोध किया था और तब एकनाथ शिंदे ने उन्हें ओवैसी की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। अब उसी उद्धव का इस विधेयक पर समर्थन देखकर लगता है कि सत्ता की भूख और अस्तित्व के दबाव ने उन्हें पुरानी राह पर ला खड़ा किया है। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से विचारधारा और सत्ता के बीच संतुलन का खेल रही है। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का आधार बनाया और उसी के दम पर शिवसेना को मजबूत किया। उद्धव ठाकरे ने 2019 में गठबंधन बदलकर सत्ता हासिल की लेकिन उसकी कीमत उनकी विचारधारा को चुकानी पड़ी।

कविता

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

उसको कितना गम है सताता

हंसता है कोई दीवारों के बाहर भी
कोई अंदर ही अंदर सुलगता है जाता
किसी के अंदर झांक कर कोई कैसे देखे
कि उसको कितना गम है सताता

बाहर से जो दिखता है वह अंदर नहीं है
अंदर वही है जो किसी को नज़र नहीं आता
वही जान सकता है जिस पर है बीत रही
ज़िंदा वही है इंसान जो दुखों से नहीं है घबराता

शांत है बाहर अंदर चल रहा भयंकर तूफान
डरता नहीं खड़ा है फिर भी सीना तान
जीतेगा वही जो करेगा डटकर मुकाबला
जिंदगी में देने पड़ते हैं कई इम्तहान

सुख दुख का तो जीवन मे लगा रहेगा आना जाना
यहाँ कोई नहीं स्थाई यह जग है एक मुसाफिर खाना
खुशियां मिलेगी किसी को किसी को मिलेगा ग़म
बीत गया जो वक्त वह फिर लौट कर नहीं है आना

आदमी जब मुसीबतों से है घिर जाता
दूर दूर तक घोर तम कुछ नज़र नहीं आता
तब दूर नज़र आती है रोशनी की एक किरण
छुप जाता है अंधेरा एक नई राह है दिखाता

परीक्षा

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़ छग

तन गई प्रत्यंचा,
खींचा गया डोर,
दागे जा रहे अक्षर-तीर
चहुं ओर,

लड़ रहे नन्हे योद्धा
अदम्य साहस के साथ,
अनजान अभी भी
नैतिक-अनैतिक
के व्यूह-पथ,

अक्षरों के ये शर
चीरते मन-मस्तिष्क की
दीवार,
फिर भी सजग हैं बच्चे,
करने प्रत्युत्तर प्रहार,

एकाग्रता का कवच ओढ़े,
संकल्पों की ढाल लिए,
क्षणिक विचलन भी यहाँ
अंधकार के द्वार दिए,

जीतना यह रण अनिवार्य,
त्यागने होंगे संशय-संघार,
हर बहाना, हर बाधा को
रखना होगा दूर अपार,

दुश्मन के वही पुराने दाँव,
पर अब सुसज्जित
है नई पीढ़ी,
ज्ञान-शस्त्रों से सुसज्जित,
लिख रही अपनी
तकदीर नई,

यह जंग लौटे हर वर्ष,
प्रश्नों के जंजाल लिए,
उत्तर बन कर काटना है
हर संशय के जाल लिए,

महायुद्ध अब भी जारी है,
विजय-किला दृष्टि में
साकार,
पताका फहराने को
साध रहे हैं वर्ष भर
का संभार।

विक्रमी संवत् 2083 के स्वागत में हर्षित धरा-गगन

प्रमोद दीक्षित मलय
नोएडा, उ.प्र.

चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात् वर्ष प्रतिपदा, यह तिथि हिन्दू काल गणनानुसार नव वर्ष के प्रारम्भ का शुभ दिन है। इस वर्ष 19 मार्च को 'रौद्र' नामक विक्रम सम्वत् 2083 का प्रथम दिवस है। प्रत्येक संवत् वर्ष का एक नाम होना, विक्रम सम्वत् की अपनी विशेषता है। 'सिद्धार्थ' नामक सम्वत् की विदाई कर लोक 'रौद्र' नामक सम्वत् का स्वागत-अभिनंदन करेगा। रौद्र नामक सम्वत् वर्ष के राजा बृहस्पति होंगे जो ज्ञान,विवेक और धर्म के कारक देव हैं तथा मंगल मंत्री के रूप में होंगे जो प्रजा में साहस,ओज और ऊर्जा का संचार करेंगे। हालांकि भारत वर्ष में विश्व के अन्य देशों की तरह मुख्य रूप से अंग्रेजी ग्रेगेरियन कलैंडर के अनुसार ही कार्य-व्यवहार संपादित होते हैं पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्कारों के निर्वहन् का आधार विक्रमी संवत् ही है। वर्तमान में विश्व में प्रचलित काल मापन प्रणालियों यथा हिन्दू, चीनी,मिस्री,पारसी,तुर्की,यहूदी, रोमन,हिजरी में हिन्दू काल गणना प्रणाली सर्वाधिक प्राचीन,प्रामाणिक, श्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। वर्ष प्रतिपदा कई ऐतिहासिक घटनाओं और संदर्भों को सहेजे हुए है। इसी दिन प्रातःकाल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारम्भ की थी। लंका विजय पश्चात् अयोध्या में श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था तो युधिष्ठिर ने भी राज्यारोहण कर अपने नाम का सम्वत् चलाया था। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव तथा सिंधी समाज के संत झूलेलाल का प्राकट्योत्सव भी है। स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना भी इसी तिथि को की थी। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी। शक्ति और भक्ति का प्रतीक पर्व चैत्रीय नवरात्र भी प्रारम्भ होता है। ग्रिगेरियन कलैंडर में 57 जोड़ने पर विक्रम संवत् मिल जाता है। नव संवत् के स्वागत में धरा-गगन आनंदित एवं हर्षित हैं। केवल हिन्दू काल प्रणाली में ही निमेष से लेकर (बल्कि उससे भी छोटी इकाईयों परमाणु,अणु, त्रसरेणु,त्रुटि,बोध,काष्ठा और लव आदि) युग,मनवन्तर और कल्प तक की गणना व्यवहार में है। किसी भी अनुष्ठान एवं सामान्य धार्मिक कर्म-काण्ड प्रारम्भ करने के पूर्व यजमान हाथ में जल,कुश,पुष्प,अक्षत आदि लेकर संकल्प करते हुए मंत्र पढ़ता है जिसमें युगाब्द,मन्वंतर,संवत्,तिथि, दिन,समय,मास आदि सहित ब्रह्माण्ड की आयु तक की गणना हमारी परम्परा में जीवनचर्या में सम्मिलित है और इस प्रकार हमने अनन्त काल-यात्रा को वर्तमान से जोड़े रखा है। हिन्दू काल गणना सूर्य,चन्द्र व पृथ्वी की गतियों पर आधृत है। एक वर्ष को 2 अयन,12 मास, 24 पक्ष, 52 सप्ताह,27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। सैकड़ों वर्षों बाद होने वाली आकाशीय घटनाओं,सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण,पूर्णमासी,अमावस्या, पर्व-त्योहार आदि की सटीक घोषणा हिन्दू पंचांग में ही सम्भव दिखायी देती है।

पंचांग से ही कुम्भ मेला के स्नान-पर्व के समय,मुहूर्त आदि की जानकारी प्राप्त कर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने, हरिद्वार,प्रयाग,उज्जैन,नासिक बिना किसी विज्ञापन एवं प्रचार के पहुँचते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति से अपरिचित विदेशियों को विस्मय में डाल देता है। ज्योतिषविद् लगध ने ग्रन्थ 'ज्योतिष वेदांग' में काल मापन की प्रणाली प्रथम बार प्रस्तुत करते हुए काल मापन के यंत्र भी बनाये।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

CMYK

शराब के नशे में दोस्त की हत्या,शव डबरी में फेंका

साले की मदद से जूट बोरी में डालकर ठिकाने लगाया शव
माता-पिता ने खून साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव डबरी में फेंकने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की उसके ही दोस्त ने डंडे और टांगी के पासा से हमला कर हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने अपने साले की मदद से शव को जूट की बोरी में डालकर गांव की डबरी में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी शीतल 15 मार्च की शाम अपने साथी टेकराम के साथ शादी समारोह में शामिल होने ग्राम पोतका गया था। जिस घर में शादी थी,उसके पड़ोस में रहने वाला प्रमोद शीतल का परिचित था। रात में शीतल प्रमोद के घर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर प्रमोद ने डंडे और टांगी के पासा से शीतल के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर

ही मौत हो गई। हत्या के बाद प्रमोद ने अपने साले राजेश कुमार की मदद से शव को जूट की बोरी में डालकर गांव के पास स्थित डबरी में फेंक दिया।

डबरी के पास मिले थे सबूत : घटना के दूसरे दिन 16 मार्च को ग्रामीणों ने डबरी के पास संदिग्ध स्थिति देखी और पुलिस को सूचना दी। उदयपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंप के माध्यम से डबरी का पानी खाली कराया और शव बाहर निकलवाया। शव की पहचान हनुमानगढ़ निवासी शीतल के रूप में हुई। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सनी जूट की बोरी, मोबाइल फोन और गमछा जब्त किया।

माता-पिता ने की साक्ष्य मिटाने की कोशिश

विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रमोद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली और बताया कि साले राजेश की मदद से शव डबरी में फेंका था। इधर आरोपी को बचाने के लिए उसकी मां पवारो और पिता बहादुर ने घर में गिरे खून के निशान साफ कर गोबर से लिपाई कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी।

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद (20 वर्ष), राजेश कुमार (20 वर्ष), पवारो (40 वर्ष) और बहादुर (42 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। चारों के खिलाफ धारा 103(1), 238(ए) और 3(5) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु आवेदन 20 मार्च तक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए जिले के पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

पात्रता एवं मापदंड- इस परीक्षा में राज्य के शासकीय विद्यालयों के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7 वीं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 5 प्रतिशत की छूट) के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही आवेदक के माता-पिता या पालक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे।

सरगुजा जिले में निर्धारित परीक्षा केन्द्र- परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु सरगुजा जिले में कुल 07 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।जिसमें शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर,शासकीय बालक उ.मा.वि. बतौली, शासकीय बालक उ.मा.वि., लखनपुर, शासकीय बालक उ.मा.वि. लुण्ड्रा, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नर्मदापुर, शासकीय बालक उ.मा.वि. सीतापुर तथा स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उदयपुर शामिल है।

आवश्यक दस्तावेज- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, कक्षा 7वीं उत्तीर्ण अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, यदि विद्यार्थी माता-पिता के स्थान पर किसी अन्य पर आश्रित है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना

संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने किया विरोध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। संघ ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को पत्र लिखकर इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने कहा कि सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों में लगभग 35 से 40 प्रतिशत पद चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के खाली हैं। ऐसे में कई संस्थानों में कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए आवश्यकता के अनुसार और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर कर्मचारियों का संलग्नीकरण किया गया है। संघ का कहना है कि यदि सभी संलग्नीकरण एक साथ समाप्त कर दिए गए तो कई स्वास्थ्य संस्थानों में काम प्रभावित होगा और आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में परेशानी होगी। संघ ने सुझाव दिया है कि जिन संस्थानों में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी पदस्थ हैं या जहां संलग्नीकरण की आवश्यकता नहीं है, वहीं से कर्मचारियों को हटाया जाए। साथ ही संस्था प्रमुखों से आवश्यकता की जानकारी लेकर ही कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाए,ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें। संघ ने जनहित में आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती होने तक संलग्नीकरण व्यवस्था जारी रखना आवश्यक है, अन्यथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

गिरने से घायल वृद्धा की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

वृद्ध महिला घर से कुछ फासले पर गिरकर अचेत हो गई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिला के प्रेमनगर थाना अंतर्गत ग्राम नमना की बिद्रा बाई पति स्व. अमर लाल 60 वर्ष, 16 मार्च की शाम को घर के परछी में खाना बना रही थी। मौके पर वृद्धा का पुत्र मदन, पुत्रवधु काजल, पोता-पोती भी मौजूद थे। इसी बीच बिद्रा बाई अपने पुत्र मदन को बाहर जा रही हूं, सब्जी देखना कहते हुए घर से बाहर निकली, और कुछ ही फासले पर गिर गई। वृद्धा की चीख-पुकार सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे, लेकिन वह बात नहीं कर रही थी। स्वजन निजी वाहन से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां इलाज के दौरान 17 मार्च को देर रात दो बजे महिला की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

नशे में महिला ने की कीटनाशक सेवन,मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

शराब का सेवन करने के बाद जहरीले पदार्थ का महिला सेवन कर ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम गेलहाचुआं, बरगवां का आनन्द टोप्पो 11 मार्च को बैल चराने के लिए गया था। घर में उसकी पत्नी सोनामनी टोप्पो 43 वर्ष अकेले थी, जो दो-तीन दिन से लगातार शराब का सेवन कर रही थी। शाम को करीब 5 बजे मवेशियों को लेकर महिला का पति आनन्द घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने और खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बैल,बकरी को बांधकर जब वह दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला, और अंदर गया तो सोनामनी पलंग के नीचे पड़ी थी, और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सिर के पास एक गिलास रखा था,जिसमें स्याही के रंग का तरल पदार्थ था। पति आननफानन में निजी वाहन की व्यवस्था करके उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे भर्ती कर लिया।

फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव का आरोप,झिरमिट्टी में शराब दुकान खोलने का ग्रामीणों ने किया विरोध

सरपंच समेत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत,कहा...बिना सहमति के खोली जा रही दुकान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरमिट्टी में प्रस्तावित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरपंच सहित ग्रामीणों ने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बनाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर सरगुजा से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब दुकान खोलने के लिए ग्राम पंचायत से कोई सहमति नहीं ली गई है। आरोप है कि सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित दिखाया गया है, जबकि इस संबंध में न तो सरपंच को जानकारी है और न ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई थी। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वे गांव में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। उनका कहना है कि शराब दुकान खुलने से गांव का माहौल खराब हो सकता है और बच्चों के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने से गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं पूरे मामले में जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि शासकीय शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव करीब एक वर्ष पहले पारित हुआ था। उस समय किसी भी ग्रामीण की ओर से कोई आपत्ति या विरोध दर्ज नहीं कराया गया था। अब जब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है, तब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। यदि ग्राम सभा प्रस्ताव में किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो इसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया नियमानुसार बताई जा रही है।

शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ
बच्चों को पिलाया गया विटामिन ए एवं आयरन सीरप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री पी एस मार्को के मार्गदर्शन में मंगलवार को शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर श्रीमती मंजूषा भगत के द्वारा बच्चों को विटामिन ए एवं आयरन सिरप पिलाकर किया गया। शुभारंभ में एमआईसी सदस्य श्रीमती ममता तिवारी, पार्षद श्रीमती किरण साहू, सिविल सर्जन डॉ जे. के,रेलवानी,जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ के पी विश्वकर्मा,जिला चिकित्सालय के स्टाफ नर्स,समस्त अधिकारी-कर्मचारी मितानिन उपस्थित रहे। बता दें शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम 17 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्यक्रम में 09 माह से वर्ष 05 के बच्चों को विटामिन ए की सिरप 06 माह के अंतराल में व 06 माह से 09 वर्ष के बच्चों को आयरन की सिरप सप्ताह में दो बार पिलाया जाएगा।

लंबित राजस्व प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निराकरण का दिया निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री वसंत ने समय-सीमा की बैठक के पश्चात राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई, वन अधिकार पत्रों का नामांतरण, कोटवारी भूमि के हस्तांतरण, आधार सीडिंग, नक्शा बटांकन, डायवर्सन, आरबीसी 6-4 के प्रकरण, हिट एंड रन सोलेसियम फंड की जानकारी, बंटवारा, त्रुटि सुधार, भूअर्जन जैसे विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने कोटवारी भूमि के हस्तांतरण की जानकारी ली तथा कहा कि अनुमति प्राप्त भूमि शासन के नाम पर आ जाए और उसमें अहस्तांतरित दर्ज कराएं। उन्होंने समय सीमा के बाहर के सभी प्रकरण को 15 दिवस में पूर्ण करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम अंतर्गत एक वर्ष एवं तहसीलदार अंतर्गत 6 माह के प्रकरण लंबित ना रहे। कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि राजस्व मामले के लिए आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो।

आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप,ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भाजपा अजजा मोर्चा के नेतृत्व में नरकालो और चोड़ेया के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नरकालो और चोड़ेया के आदिवासी ग्रामीणों ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र सौंपा है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की। भाजपा अजजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी लाल पैकरा ने बताया कि नरकालो और चोड़ेया गांव के निवासी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति से हैं, जो कई पीढ़ियों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर निवास करते आ रहे हैं। उनका जीवनयापन,संस्कृति और धार्मिक आस्था पूरी तरह जल,जंगल और जमीन पर निर्भर है। यह क्षेत्र भी पांचवीं अनुसूची में शामिल है,जहां आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान लागू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार के नवादा सहित अन्य क्षेत्रों से आए कुछ लोगों द्वारा गांव की आदिवासी जमीन पर जबरन मकान निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है और बिना वैधानिक अधिकार के स्थायी रूप से बसावट की जा रही है।

कई ग्रामीणों की जमीन पर कब्जे का आरोप : पैकरा ने बताया कि नरकालो निवासी बदलू की करीब एक एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है। इसी तरह गिरीश की लगभग 87 डिसमिल जमीन,बसंती कंवर की करीब डेढ़ एकड़ भूमि और घूरऊ कंवर की जमीन पर भी कब्जे का आरोप लगाया गया है। वहीं ग्राम चोड़ेया में भी कुछ ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई है।

विरोध करने पर दी जाती है धमकी : अजजा मोर्चा के महामंत्री रविकांत उरांव ने कहा कि जब आदिवासी ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है और मारपीट की धमकी दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर और अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर हो रहे कब्जों से उनकी कृषि भूमि कम होती जा रही है, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही है। साथ ही गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सूरजपुर में हाथी की मौत पर केंद्र सख्त....7 साल में 63 हाथियों की मौत से मचा हड़कंप,छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक हाथी की संदिग्ध मौत ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, घटना के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, खास बात यह है कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में 63 हाथियों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी है।

क्या है ताजा मामला?- सूरजपुर जिले में हाल ही में एक हाथी मृत अवस्था में पाया गया, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत की परिस्थितियां संदिग्ध हैं, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है,मौत के कारणों को लेकर कई संभावनाएं जताई जा रही हैं बिजली के करंट से मौत,जहर देने की आशंका या किसी अन्य दुर्घटना, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत कैसे हुई।

केंद्र सरकार की सख्ती- घटना के बाद केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी है, इसमें निम्न बिंदुओं पर जानकारी देने को कहा गया है हाथी की मौत का वास्तविक कारण,घटनास्थल की स्थिति और परिस्थितियां,संबंधित अधिकारियों की भूमिका,भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय केंद्र की इस सख्ती से साफ है कि अब इस मामले को केवल औपचारिक जांच तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

63 हाथियों की मौत — बड़ा संकेत- पिछले 7 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 63 हाथियों की मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है, इन मौतों के पीछे प्रमुख कारण माने जा रहे हैं,बिजली के करंट से हादसे,ट्रेन से टकराव,जहर,प्राकृतिक कारण,और सबसे अहम, मानव-हाथी संघर्ष यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में हाथियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं।

मानव-हाथी संघर्ष बढ़ा संकट- विशेषज्ञों का मानना है कि हाथियों की मौत का सबसे बड़ा कारण मानव-हाथी संघर्ष है,जंगलों का लगातार सिकुड़ना, हाथियों के प्राकृतिक रास्तों (कॉरिडोर) का बाधित होना,खेतों और गांवों में हाथियों का प्रवेश इन कारणों से टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं,कई बार किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बिजली के तार या अन्य खतरनाक उपाय अपनाते हैं,जिससे हाथियों की मौत हो जाती है।

वन विभाग की तैयारियों पर सवाल- लगातार बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, मुख्य सवाल क्या हाथियों की निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? क्या संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते अलर्ट जारी किए जाते हैं? क्या ग्रामीणों को पर्याप्त जागरूक किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम के बजाय अक्सर विभाग घटना के बाद सक्रिय होता है, जो कि पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण भी संकट में- इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह है कि ग्रामीण भी इस संघर्ष में प्रभावित हो रहे हैं, हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान, जान-माल का खतरा, रात के समय गांवों में घुसपैठ,इन समस्याओं के कारण ग्रामीणों में भय और असंतोष बढ़ रहा है,कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें समय पर मुआवजा नहीं मिलता, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

क्या हैं समाधान?- विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति को सुधारने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए...

- हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा और पुर्नस्थापना
- बिजली लाइनों को सुरक्षित बनाना
- अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना
- ग्रामीणों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- त्वरित मुआवजा व्यवस्था

चेतावनी का संकेत- सूरजपुर में हाथी की मौत एक अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि एक बड़े संकट का संकेत है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में हाथियों की मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं।

अंत में सबसे बड़ा सवाल

क्या यह मामला सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित रहेगा,या वास्तव में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी बदलाव देखने को मिलेगा?

धान के चबूतरे के नीचे दबा सच...सरगुजा में 'संरक्षण तिगड़ी' के साये में खरीदी का खेल?

धान खरीदी या संरक्षण उद्योग? सरगुजा में तिगड़ी के साये में सिस्टम

निलंबन,एफआईआर के बाद भी नहीं थमा खेल भैयाथान-लटोरी बना सबसे बड़ा उदाहरण

धान के चबूतरे के नीचे दबा सच : सरगुजा में 'संरक्षण तिगड़ी' का खेल

निलंबन,एफआईआर...फिर भी बेखौफ : धान खरीदी में किसका संरक्षण?

93 लाख से लेकर ऋण घोटाले तक: कार्रवाई हुई या सिर्फ दिखावा?

केंचुए की चाल में न्याय : गड़बड़ी साबित,सजा गायब

धान खरीदी या संरक्षण उद्योग? सरगुजा मॉडल पर बड़ा सवाल

सीईओ श्रीकांत चंद्राकर,संयुक्त आयुक्त सुनील तिवारी और अध्यक्ष किशन राम सिंह पर उठे सवाल

फाइलें दबती रहीं,सिस्टम चलता रहा – किसान भरोसा खोता गया

धान खरीदी में 'मैनेजमेंट राज': पकड़ो,दबाओ और आगे बढ़ जाओ

फाइलों में दफन घोटाले : सरगुजा में कौन बचा रहा किसे?

गड़बड़ी पकड़ने वाले ही कटघरे में : सहकारिता तंत्र पर बड़ा सवाल

धान के नाम पर खेल,किसान के नाम पर धोखा?

संरक्षण की छतरी में फलता-फूलता भ्रष्टाचार...

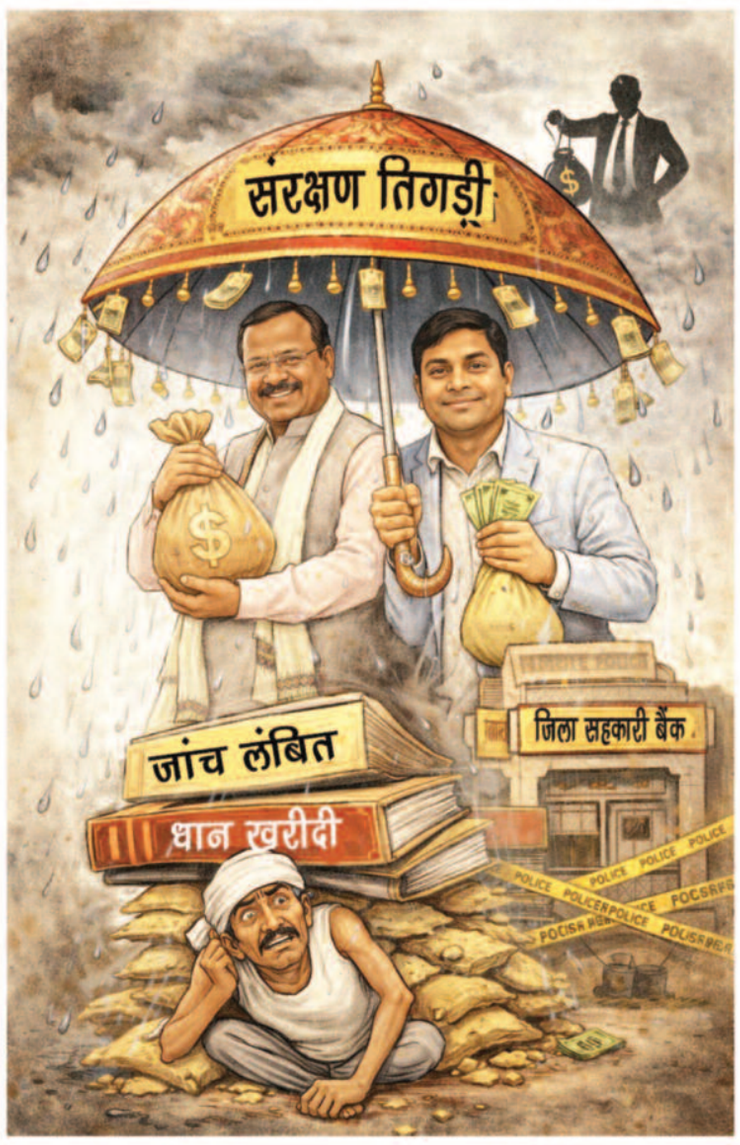

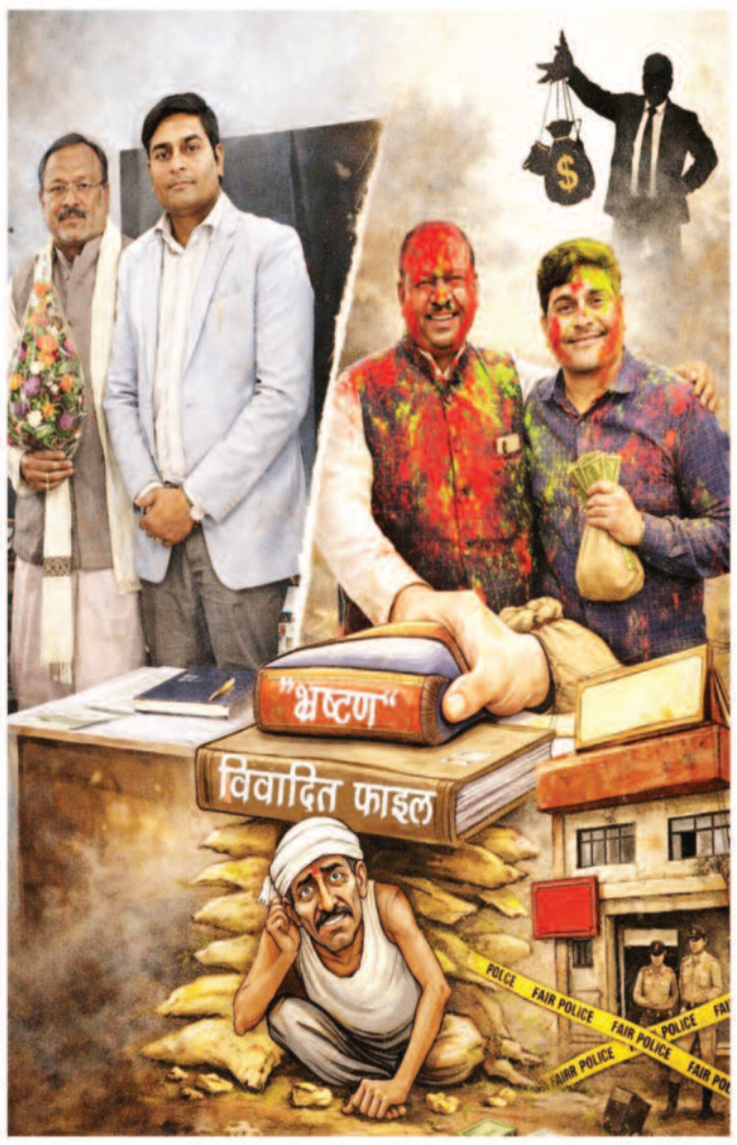

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ का किसान जब धान की बोरियां लेकर खरीदी केंद्र पहुंचता है,तो उसे सिर्फ कीमत नहीं,बल्कि व्यवस्था पर भरोसा चाहिए होता है,यही भरोसा राज्य की धान खरीदी प्रणाली की असली पूंजी है,लेकिन सरगुजा संभाग से उठ रही खबरें इस भरोसे को लगातार कमजोर कर रही हैं,यह मामला अब साधारण अनियमितताओं से आगे बढ़कर एक पैटर्न,एक सिस्टम और कथित 'संरक्षण मॉडल' की कहानी बन चुका है,इस पूरे प्रकरण में जिन तीन नामों की चर्चा लगातार सामने आ रही है,उन्हें स्थानीय स्तर पर व्यंग्य में 'संरक्षण तिगड़ी' कहा जा रहा है,जिनमे सीईओ श्रीकांत चंद्राकर (जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, अंबिकापुर),संयुक्त आयुक्त सहकारिता सुनील तिवारी (संयुक्त पंजीयक,सरगुजा संभाग), प्राधिकरण अध्यक्ष किशन राम सिंह आरोपों की आधिकारिक पुष्टि भले न हो,लेकिन घटनाओं की श्रृंखला,फाइलों की गति और कार्रवाई की स्थिति ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अध्याय 1 : धान खरीदी – व्यवस्था की ताकत या कमजोरी का आईना?

छत्तीसगढ़ की धान खरीदी प्रणाली देश में एक मॉडल मानी जाती है,सहकारी समितियां,जिला सहकारी बैंक और प्रशासन मिलकर इस व्यवस्था को संचालित करते हैं,इस प्रणाली के मुख्य उद्देश्य हैं की किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी,समय पर भुगतान, पारदर्शी रिकॉर्ड,सुरक्षित भंडारण,लेकिन सरगुजा संभाग में इन मूल उद्देश्यों की जगह अब चर्चा हो रही है गड़बड़ी,देरी,फाइल दबने और संरक्षण की।

अध्याय 2 : सूरजपुर-गड़बड़ी की खबरें और गायब होती कार्रवाई

सूरजपुर जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में समय-समय पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई, इनमें प्रमुख आरोप रहे,स्टॉक और रिकॉर्ड में अंतर, धान की मात्रा में हेरफेर,बीमा क्लेम राशि में गड़बड़ी, परिवहन प्रक्रिया में अनियमितता जांच के दौरान कुछ मामलों में गड़बड़ी प्रमाणित भी हुई,लेकिन इसके बाद कार्रवाई की गति संदिग्ध रही,फाइलों की स्थिति पर स्थानीय लोग कहते हैं की यहां फाइलें चलती हैं, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं।

अध्याय 3 : 'केंचुए की चाल' जांच की परिभाषा बदल गई

सरकारी जांच की धीमी रफ्तार कोई नई बात नहीं, लेकिन यहां यह एक 'व्यवस्था' बन चुकी है,जांच शुरू होती है,नोटिंग होती है,फाइल आगे बढ़ती है और फिर महीनों तक स्थिर स्थानीय शब्दों में 'केंचुए की चाल वाली जांच' इसका असर ये होता है की दोषियों में डर खत्म,ईमानदारों में निराशा और सिस्टम में भरोसे की कमी।

अध्याय 4 : शिवप्रसादनगर गड़बड़ी का प्रतीक...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को इस पूरे सिस्टम का 'केस स्टडी' माना जा रहा है, यहां गड़बड़ी की शिकायतें,बीमा विवाद,निलंबन और जांच सब कुछ हुआ,लेकिन अंतिम परिणाम? अस्पष्ट रहा,स्थानीय व्यंग्य है की 'यहां धान से ज्यादा फाइलें दबती हैं।

अध्याय 5 : उदाहरण जो पूरा सिस्टम समझाता है 'निलंबन,एफआईआर और फिर संरक्षण?' – भैयाथान-लटोरी शाखा का पूरा मामला

यदि सरगुजा संभाग में 'संरक्षण मॉडल' को समझना हो,तो जिला सहकारी बैंक की भैयाथान-लटोरी शाखा इसका सबसे सटीक उदाहरण बनती है,यहां घटनाएं एक-दो साल की नहीं,बल्कि लगातार कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं।

2019 : धान खरीदी में 93.41 लाख की गड़बड़ी

कलेक्टर कार्यालय सूरजपुर द्वारा जारी पत्र में ?93,41,000 की वित्तीय अनियमितता, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश,पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई आदेश यह स्पष्ट संकेत था कि मामला गंभीर है,लेकिन बड़ा सवाल क्या किसी को सजा मिली?

2022 : गोपालन ऋण नियमों की अनदेखी

शिकायतों के आधार पर जांच टीम गठित हुई, जांच में पाया गया की पात्रता से अधिक ऋण,लाभार्थियों की जांच में कमी, नियमों का उल्लंघन।

पैटर्न जो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है...

घटनाओं को जोड़ें—

1. 2019 – धान खरीदी गड़बड़ी
2. 2022 – ऋण अनियमितता
3. 2023 – एफआईआर
4. फिर भी – प्रभाव कायम यह एक पैटर्न बनाता है– 'कार्रवाई होती है,लेकिन परिणाम नहीं।

चौंकाने वाले आरोप....

- मृत व्यक्तियों के नाम पर ऋण
- पात्रता से अधिक राशि
- चयनित लाभार्थियों को फायदा यदि ये आरोप सही हैं,तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विफलता है।

कानूनी स्थिति – गंभीर धाराएं, हल्का परिणाम?

धारा 409 (विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) जैसे गंभीर आरोप लगे। लेकिन—

- चार्जशीट की स्थिति अस्पष्ट
- ट्रायल की जानकारी सीमित
- सजा का रिकॉर्ड सामने नहीं

किसानों की आवाज...

कई किसानों ने बताया की ऋण में देरी,भुगतान में अड़चन,अनावश्यक कागजी प्रक्रिया,वहीं कुछ मामलों में तेज स्वीकृति व अधिक राशि प्रकिरिया बनी रही।

2023 : एफआईआर और निलंबन

- 04 जनवरी 2023-एफआईआर दर्ज (धारा 409,420,34 आईपीसी)
- 27 जनवरी 2023-निलंबन आदेश जारी यहां तक सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार था।
- **लेकिन इसके बाद... 'संरक्षण की चर्चा'** – सूत्रों और कर्मचारियों का दावा निलंबन के बाद भी प्रभाव बना रहा, कठोर कार्रवाई नहीं हुई,बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई सामने नहीं आई, यहां निलंबन अंत नहीं,एक औपचारिकता है।

अध्याय 6 : 'संरक्षण तिगड़ी'

सवालों के घेरे में शीर्ष स्तर-अब सवाल फिर वहीं लौटता है जब यह सब वर्षों से चल रहा है,तो निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या संरक्षण ऊपर तक फैला है? स्थानीय व्यंग्य है की यहां फाइल ऊपर जाती है और सच नीचे दब जाता है।

अध्याय 7 : शादी,वसूली और 'संरक्षण नेटवर्क'- सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण अध्यक्ष किशन राम सिंह के पारिवारिक कार्यक्रम में खरीदी केंद्रों से आर्थिक सहयोग संरक्षण का संकेत हालांकि पुष्टि नहीं,लेकिन चर्चा व्यापक है।

अध्याय 8 : 'पुराना खिलाड़ी'- सिस्टम का अनौपचारिक संचालक- एक पूर्व बैंक मैनेजर का नाम भी चर्चा में है संपर्क सूत्र मैनेजमेंट एक्सपर्ट व नेटवर्क का हिस्सा है।

अध्याय 9 : राजनीति बनाम-किशन राम सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं की क्या राजनीतिक प्रभाव कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है? क्या सहकारिता तंत्र स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है?

अध्याय 10: किसान-सबसे बड़ा नुकसान

इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान–

- किसान
- भरोसा
- पारदर्शिता

धान खरीदी या 'संरक्षण उद्योग'?

सरगुजा में अब यह सवाल आम हो चुका है की यह धान खरीदी है या संरक्षण उद्योग? जहां गड़बड़ी होती है,जांच होती है,फाइल दबती है और सिस्टम चलता रहता है।

आखिरी सवाल (जो जवाब मांगता है)

- **क्या स्वतंत्र जांच होगी?**
- **क्या जिम्मेदार तय होंगे?**
- **क्या सजा मिलेगी? या फिर— 'यह मामला भी धान के चबूतरे के नीचे दब जाएगा?'**
- **क्योंकि अब सवाल सिर्फ धान का नहीं... विश्वास का है।**

चैत्र नवरात्रि पर भक्ति और संस्कृति का संगम कुदरगढ़ महोत्सव में गूंजेंगे सुर और श्रद्धा

सीर्ली सेटिया समेत स्थानीय व छत्तीसगढ़ी कलाकार देंगे शानदार प्रस्तुतियां

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

चैत्र नवरात्रि की पावन बेला में माता कुदरगढ़ी की पवित्र धरा एक बार फिर भक्ति,संस्कृति और उत्सव की रंगत से सराबोर होने जा रही है,सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदरगढ़ में 23 मार्च से 25 मार्च 2026 तक तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा।

आस्था और उत्सव के इस अद्भुत संगम में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु,नागरिक और संस्कृति प्रेमी शामिल होंगे,नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव धार्मिक श्रद्धा के साथ-साथ लोक संस्कृति और कला का भी शानदार मंच बनेगा।

भजन और संगीत से गुंजेगा पूरा कुदरगढ़- महोत्सव के पहले दिन 23 मार्च को सुप्रसिद्ध 'भजन बैंड-लीला' अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर देंगे,भजन और देवी गीतों की मनमोहक प्रस्तुति श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर देगी,महोत्सव के समापन दिवस 25 मार्च को प्रसिद्ध गायिका सीर्ली सेटिया अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। उनके गीतों की प्रस्तुति इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण मानी जा रही है,जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा मंच- तीनों दिन स्थानीय व छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा भी भक्तिमय और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी,इन प्रस्तुतियों के माध्यम से क्षेत्र की लोक परंपराओं,लोकगीतों और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक देखने को मिलेगी,इस तरह कुदरगढ़ महोत्सव न केवल भक्ति का पर्व होगा बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को मंच देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन भी बनेगा।

दोपहर से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम- यह तीन दिवसीय महोत्सव ग्राम पंचायत कुदरगढ़,विकासखंड ओड़गी, जिला सूरजपुर में आयोजित किया जाएगा, प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी,जो देर शाम तक जारी रहेंगे और दर्शकों को बांधे रखेंगे।

प्रशासन ने नागरिकों से की अपील- जिला प्रशासन सूरजपुर ने जिले के सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कर महोत्सव को भव्य और सफल बनाएं तथा भक्ति और संस्कृति के इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनें।

भाजपा आईटी सेल को मिला नया नेतृत्व एजाज अहमद बने बलरामपुर जिला प्रभारी

-संवाददाता-
सूरजपुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अपने आईटी सेल के विस्तार की घोषणा करते हुए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डे ने यह सूची जारी की,जारी सूची के अनुसार प्रदेश आईटी सेल संयोजक सुनील पिल्लई के नेतृत्व में संगठन को डिजिटल स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से कई कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं,इसी क्रम में सूरजपुर जिले के एजाज अहमद को बलरामपुर जिले का आईटी सेल प्रभारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि एजाज अहमद लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी सक्रियता व निष्ठा को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है,वे इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और दो बार आईटी सेल के जिला संयोजक के पद का दायित्व भी संभाल चुके हैं। संगठनात्मक अनुभव और डिजिटल कार्यों में उनकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश स्तर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, एजाज अहमद की नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके नेतृत्व में आईटी सेल संगठन की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा, अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए एजाज अहमद उर्फ जिम्मी ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है,उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे,उन्होंने कहा कि वे आईटी सेल के माध्यम से संगठन को डिजिटल स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे,जिला प्रभारी बनाए जाने पर एजाज अहमद ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी,मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े,मंत्री रामविचार नेताम, विधायक भुलन सिंह मरावी, विधायक शकुंतला पोर्ते तथा वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में संगठनात्मक कार्यों को और अधिक गति दी जाएगी।

आदिवासी छात्रावासों में अव्यवस्था...

जिम्मेदार सिर्फ अधीक्षक या मॉनिटरिंग तंत्र भी कटघरे में?

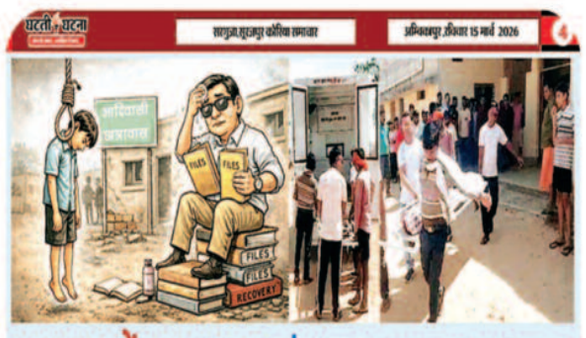

घटती घटना
सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार
अम्बिकापुर,रविवार 15 मार्च 2026
4

छात्रावास में व्यवस्था का फंदा या आत्महत्या का सच ?

सोनहत के आदिवासी छात्र की मौत ने खोल दी सिस्टम की परतें

20 दिन पहले छात्र ने मीडिया के सामने खोली थी छात्रावास की अव्यवस्थाओं की पोल

- छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर बोला छात्र...20 दिन बाद फांसी के फंदे पर मिला
- खबर छपने के बाद पहुंचे थे अधिकारी,लेकिन क्या बदली कोई व्यवस्था?
- घर जाने की जिद कर रहा था छात्र,अनुमति नहीं मिली : सूत्र
- सवाल बड़ा: अव्यवस्थाओं पर बोलना क्या छात्र के लिए 'अपराध' बन गया?
- छात्रावास में व्यवस्था नहीं,सन्नाटा...11 वीं के छात्र ने लगाई फांसी...
- निरीक्षण हुआ,आश्वासन मिला...लेकिन एक छात्र की जिंदगी चली गई...
- व्यवस्था पर सवाल उठाने की कीमत? आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत...

घटती घटना
कोरिया- सूरजपुर समाचार
अम्बिकापुर,मंगलवार 17 मार्च 2026
5

सुरक्षा के दावे फेल,छात्रावास में छात्र ने लगाई फांसी

आदिवासी छात्रावास: सपनों का घर या भ्रष्टाचार का अड्डा?

व्यवस्था कटघरे में...

- आदिवासी छात्रों का भविष्य या भ्रष्टाचार की फैक्ट्री? सोनहत की घटना से खुला राज
- आदिवासी छात्रावास या मौत का अड्डा? सोनहत में छात्र की फांसी ने खोली व्यवस्था की पोल
- छात्रावास में लटक गया सपना : आदिवासी छात्र की मौत ने उठाए बड़े सवाल
- छात्रों के नाम पर पैसा,सुविधाओं में कटौती और अंत में मौत! सोनहत छात्रावास पर गंभीर सवाल
- सपनों के घर में मौत : आदिवासी छात्रावास की हकीकत आई सामने
- सुविधाओं की जगह सौदेबाजी? छात्रावास में सीटों से लेकर सुविधाओं तक 'बोली' का खेल
- सरकारी योजना या गोरखधंधा? आदिवासी छात्रावास पर उठे तीखे सवाल

आदिवासी छात्रावास योजना उद्देश्य और वास्तविकता के बीच खाई

प्रति छात्र मिलने वाली राशि में कथित बंदरबांट...

अतिरिक्त सीटों के नाम पर कमाई का खेल

छात्रावास में मौत,सवाल सहायक आयुक्त पर...ढाई साल में क्यों नहीं सुधरी व्यवस्था ?

अधीक्षक दोषी या सिस्टम ? कोरिया के छात्रावासों पर उठे जवाबदेही के बड़े सवाल

छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे ? कोरिया के छात्रावासों में अव्यवस्था की लंबी कहानी

ढाई साल का कार्यकाल और घटनाओं की श्रृंखला...सहायक आयुक्त की निगरानी पर सवाल

छात्रावासों में अव्यवस्था,जांच अधीक्षक पर मॉनिटरिंग करने वाले क्यों बाहर ?

सुविधा छात्रों के लिए,जिम्मेदारी किसकी ? कोरिया छात्रावास व्यवस्था पर बड़ा सवाल

सोनहत की घटना ने खोली परतें...छात्रावास व्यवस्था में निगरानी तंत्र पर सवाल

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/ सोनहत, 17 मार्च 2026 (घटती-घटना)। आदिवासी समुदाय के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा आश्रम छात्रावास और एकलव्य विद्यालयों की व्यवस्था की गई है,इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी छात्र आर्थिक अभाव या शैक्षणिक संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहें, सरकार इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवास,भोजन,अध्ययन का वातावरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि वे सुरक्षित माहौल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

लेकिन जब ऐसी व्यवस्था, जो आदिवासी छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई हो, लगातार शिकायतों, अव्यवस्थाओं और गंभीर घटनाओं की वजह से चर्चा में आने लगे, तब सवाल केवल छात्रावासों की व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि उसकी निगरानी करने वाली पूरी प्रशासनिक संरचना पर भी खड़े होने लगते हैं, कोरिया जिले में पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी छात्रावासों को लेकर लगातार शिकायतें और घटनाएं सामने आती रही हैं,हाल ही में सोनहत क्षेत्र के एक छात्रावास में एक छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया, इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर छात्रावास व्यवस्था की जवाबदेही किसकी है, केवल अधीक्षक की या फिर उन अधिकारियों की भी जो पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं।

वसूली और बंदरबांट की चर्चा

स्थानीय सूत्रों के अनुसार छात्रावास व्यवस्था में प्रति छात्र मिलने वाली राशि में कथित तौर पर मासिक और वार्षिक वसूली का खेल भी चलता है,यदि यह आरोप सही हैं तो यह व्यवस्था के लिए किसी दीमक से कम नहीं है, क्योंकि यही व्यवस्था धीरे-धीरे छात्रावासों की गुणवत्ता और सुविधाओं को कमजोर कर देती है।

अधीक्षक ही दोषी या पूरी व्यवस्था ?

जब भी किसी छात्रावास में गड़बड़ी सामने आती है तो अक्सर कार्रवाई अधीक्षक तक सीमित रह जाती है,लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि निगरानी की व्यवस्था मजबूत होती तो क्या इतनी घटनाएं सामने आतीं? क्योंकि अधीक्षक के ऊपर भी एक प्रशासनिक ढांचा होता है,जिसकी जिम्मेदारी निगरानी और सुधार की होती है।

जवाबदेही तय करना जरूरी

सोनहत की घटना के बाद यह सवाल और तेज हो गया है कि यदि छात्रावासों में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं तो जिम्मेदारी तय कैसे होगी,क्या केवल अधीक्षक को दोषी ठहराकर व्यवस्था में सुधार संभव है? या फिर उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा भी आवश्यक है जो इन छात्रावासों की निगरानी के लिए बनाई गई है?

सहायक आयुक्त की भूमिकाः निगरानी या केवल औपचारिकता ?

आदिवासी विकास विभाग में प्रत्येक जिले में सहायक आयुक्त की नियुक्ति इसलिए की जाती है ताकि वे जिले के सभी आश्रम छात्रावासों और आदिवासी विद्यालयों की निगरानी कर सकें, सहायक आयुक्त की जिम्मेदारियों में शामिल होता है, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण,छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा, शिकायतों का समाधान, अधीक्षकों की कार्यप्रणाली की निगरानी,छात्रों की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना, लेकिन यदि लगातार छात्रावासों से शिकायतें आती रहें, सुविधाओं में कमी की बातें सामने आएं और गंभीर घटनाएं घटती रहें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह निगरानी केवल कागजों में सीमित रह गई है या वास्तव में जमीनी स्तर पर भी हो रही है।

ढाई वर्षों का कार्यकाल और घटनाओं की लंबी सूची...

कोरिया जिले में वर्तमान सहायक आयुक्त का कार्यकाल लगभग ढाई वर्षों का हो चुका है,इस दौरान जिले के आश्रम छात्रावासों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं,ऐसा शायद ही कोई वर्ष रहा हो जब छात्रावासों की व्यवस्था को लेकर कोई विवाद,शिकायत या गंभीर घटना सामने न आई हो,कभी छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की चर्चा हुई,तो कभी छात्र सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, कई बार छात्रों को अपनी समस्याएं सामने लाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा, हालिया घटना सोनहत के एक छात्रावास की है, जहां एक छात्र ने छात्रावास परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली,हालांकि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आत्महत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या था, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है,क्या छात्रावासों में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति की निगरानी वास्तव में की जा रही है?

मुखर छात्र और दुःखद अंत

बताया जा रहा है कि जिस छात्र ने आत्महत्या की, वह छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर मुखर था और अपनी समस्याओं को मीडिया के माध्यम से सामने लाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी स्थिति में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या उसे अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया या फिर उस पर दबाव की स्थिति बनी? यदि कोई छात्र अपनी समस्याओं को सामने लाता है तो उसे संरक्षण मिलना चाहिए या उसे चुप कराने का प्रयास होना चाहिए–यह सवाल अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

पहले भी सामने आ चुकी हैं गंभीर घटनाएं

सोनहत की घटना को यदि अलग रख भी दिया जाए, तब भी कोरिया जिले के छात्रावासों का रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक ही दिखाई देता है, इस दौरान कई तरह की घटनाएं सामने आईं,छात्रावासों में अव्यवस्था की शिकायतें, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप, सुरक्षा को लेकर सवाल, छात्राओं से जुड़े संवेदनशील मामले, एक मामले में तो छात्रावास से जुड़ी घटना के बाद एक छात्रा द्वारा अपने घर जाकर आत्महत्या करने की खबर भी सामने आई थी, इन घटनाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार न होना प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है।

खरीद और निर्माण में भी अनियमितता की चर्चा

सूत्रों के अनुसार सहायक आयुक्त के कार्यकाल के दौरान छात्रावासों में सामग्री खरीदी और निर्माण कार्यों को लेकर भी कई बार अनियमितताओं की चर्चा सामने आई है, अमानक सामग्री की खरीदी, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी और निगरानी के अभाव जैसे आरोप भी समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं, तड़ित चालक (लाइटनिंग अरेस्टर) जैसी सुरक्षा व्यवस्था की खरीदी को लेकर भी सवाल उठे थे, बताया जाता है कि कई छात्रावासों में लगाए गए तड़ित चालक टिकाऊ साबित नहीं हुए और कुछ जगह तो यह लगते ही बेअसर हो गए, यदि यह सच है तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी है।

पदोन्नति और पोस्टिंग का विवाद

इसी कार्यकाल के दौरान छात्रावास अधीक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर भी विवाद सामने आया, स्थिति इतनी उलझ गई कि पुनः काउंसलिंग कराकर पोस्टिंग आदेश जारी करने पड़े, उस समय यह चर्चा भी सामने आई कि कई अधीक्षक अधिक सीट वाले छात्रावासों में पदस्थापना को लेकर विशेष रुचि दिखा रहे थे, स्थानीय स्तर पर इसे लेकर यह टिप्पणी भी सुनने को मिली कि जहां छात्र ज्यादा, वहां जिम्मेदारी कम और सुविधाओं की संभावनाएं ज्यादा समझी जाती हैं, यदि ऐसी मानसिकता विकसित हो जाए तो छात्रावास व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।

अंत में

कोरिया जिले में आदिवासी छात्रावासों को लेकर उठ रहे सवाल केवल प्रशासनिक बहस का विषय नहीं हैं, यह उन हजारों आदिवासी छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है जो इन छात्रावासों में रहकर बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे हैं,यदि इन छात्रावासों की व्यवस्था में पारदर्शिता,निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई,तो यह केवल एक योजना की विफलता नहीं होगी बल्कि उन छात्रों के सपनों के साथ भी अन्याय होगा जिनके लिए यह पूरी व्यवस्था बनाई गई है, अब जरूरत इस बात की है कि इन घटनाओं को केवल अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय पूरी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए और जिम्मेदारी वहां तय की जाए जहां वास्तव में तय होनी चाहिए।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज मुख्यालय बलरामपुर (छ0ग0)

फोन नम्बर 07831-299063 ई-मेल :-acbalrampur@gmail.com

:: शुद्धिपत्र सूचना पत्र ::

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3663/निर्माण आ.वि./2026 बलरामपुर, दिनांक 27.02.2026 के तहत निविदा क्रमांक 183036 कार्य का नाम- प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बलरामपुर भवन निर्माण लागत राशि 24,06,00,000-00 (रूपये चौबीस करोड़ छः लाख मात्र) जारी किया गया है। जिसका रिफरेन्स नंबर 252603008387 तथा एडवरटाईज नंबर जी-252607032/7 है ।

उक्त निविदा के एन.आई.टी एवं अन्य दस्तावेजों में सुधार कर अपलोड कर दिया गया है,जिसे वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in/ में देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
बलरामपुर-रामानुजगंज

जी नंबर-252607194/4

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर -3 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क0:202603022900006 /अ-27 / 25-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार साण्डिल्य आ0 स्व. गोविन्द राम नाई निवासी ग्राम नवागढ़, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा ग्राम नवागढ़ स्थित स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ख0न0 188/1 रकबा 1.147 हे0 भूमि का उभयपक्ष के मध्य 1/6 अंश में बंटवारा कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 06/04/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 13/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर -3 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क0: 202603022900007 /अ-27 / 25-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार साण्डिल्य आ0 स्व. गोविन्द राम नाई निवासी ग्राम नवागढ़, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा ग्राम नवागढ़ स्थित स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ख0न0 189/1 रकबा 0.138 हे0 भूमि का उभयपक्ष के मध्य 1/3 अंश में बंटवारा कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 06/04/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 13/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

सामान्य वन मंडल धरमजयगढ़ (छ.ग.)

:: ई-नीलाम विज्ञापन ::

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वन मंडल धरमजयगढ़ के काष्ठागार धरमजयगढ में उपलब्ध ईमारती एवं जलाऊ लकडी का दर्शित तिथि समय में ई-नीलाम किया जावेगा ।

1. ई-नीलाम दिनांक - 23-03-2026
2. ई-नीलाम समय - प्रातः 09:00 बजे से प्रारंभ

अ. क.	प्रजाति	नया वनोपज		पुराना वनोपज		योग वनोपज	
		लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0	0	129.971	0	129.971	0
2	साल	420.000	500	2641.983	2966	3061.983	3466
3	बीजा	5.000	0	161.536	0	166.536	0
4	खम्हार	0	0	0.932	0	0.932	0
5	साजा	10.000	105	71.542	860	81.542	965
6	हल्दू	0	0	19.782	0	19.782	0
7	धावड़ा	5.000	78	11.403	131	16.403	206
8	सलिहा	0	0	7.915	0	7.915	0
9	अन्य	8.000	0	276.665	1574	284.665	1574
10	आर.टी.एल	0	0	0	0	0	0
	योग :–	448.000	683	3321.729	5531	3769.729	6214
11	जलाऊ	583 चट्टा	–	3052 चट्टा	0	3635 चट्टा	–

अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे ई-नीलाम में भाग लेवें। ई-नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय में डिपो से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त मात्रा में कमी - अधिकता संभव है।

जी नंबर-252607215/4

वनमण्डलाधिकारी,
धरमजयगढ़ वनमण्डल

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर.जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/202508021200099 /अ-6-अ/2024-25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण अल्पना गुप्ता पति स्व0 जयंत गुप्ता, राजुल कुमार गुप्ता आ0 स्व0 जयंत गुप्ता, निवासी वसुन्धरा विहार गोधनपुर,अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-अंधारी बगीचा,नगर अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर शीट नंबर- 03 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 1146/4 रकबा 18×130 = 2340 वर्गफीट एवं नजूल भूखण्ड क्रमांक 2067/13 रकबा 25×225 = 5625 वर्गफीट भूमि के नक्शा बटांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूमि के नक्शा बटांकन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख अम्बिकापुर द्वारा नक्शा बटांकन हेतु प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया गया है। जो एतद् संलग्न है।

उक्त भू-खण्ड का प्रस्तावित नक्शा अनुसार नक्शा बटांकन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-02/04/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

सोनहत अस्पताल में 'कायाकल्प' की क्रांति

सरकारी सिस्टम का ऐसा रूप, जिसे देखकर प्राइवेट अस्पताल भी हो जाएं असहज

सोनहत अस्पताल का कायाकल्प...सरकारी सिस्टम बना 'कॉर्पोरेट' से भी बेहतर!

जहां कभी थी बदहाली, अब हाई-टेक इलाज–सोनहत अस्पताल ने लिखी नई इबारत

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का असर,सोनहत अस्पताल बना भरोसे का सबसे बड़ा केंद्र

प्राइवेट अस्पतालों को टक्कर देता सोनहत CHC , सुविधाओं में दिखा बड़ा बदलाव

मोतियाबिंद ऑपरेशन से डिजिटल एक्स-रे तक–सोनहत में इलाज अब 'वन स्टॉप'

बदली तस्वीरः अस्पताल में कदम रखते ही दिखता है बदलाव

अब सोनहत अस्पताल में प्रवेश करते ही जो दृश्य सामने आता है, वह किसी निजी या कॉर्पोरेट अस्पताल से कम नहीं।

हाई-टेक ओपीडी काउंटर : मरीजों का कंप्यूटरीकृत पंजीकरण,बिना धक्का-मुक्की के सुव्यवस्थित प्रक्रिया

सुसज्जित इमरजेंसी वार्ड : गंभीर मरीजों को तत्काल प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था

डॉक्टरों के आधुनिक कक्ष : बेहतर कार्य वातावरण,जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार, पहले जहां मरीजों को भटकना पड़ता था,अब पूरी व्यवस्था सिस्टमेटिक और पेशेंट फ्रेंडली बन चुकी है।

-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया), 17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

कभी बदहाली,संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के लिए चर्चा में रहने वाला सोनहत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज एक नई पहचान, नई ऊर्जा और नई कार्यसंस्कृति के साथ उभरकर सामने आया है, यह बदलाव इतना व्यापक है कि अब यहां आने वाले मरीजों को यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही सरकारी अस्पताल है, जहां कभी इलाज से ज्यादा इंतजार और असुविधा मिलती थी। आज सोनहत अस्पताल न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है,बल्कि यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के उस नए मॉडल का उदाहरण बन गया है,जहां इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सख्ती और जमीनी मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकती है,इस परिवर्तन के केंद्र में हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,जिनके स्पष्ट निर्देश–सरकारी अस्पतालों को भरोसे का केंद्र बनाना है–ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। उनके विजन को जमीन पर उतारने में सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह और बीएमओ डॉ. बलवंत सिंह की सतत निगरानी और मेहनत ने निर्णायक भूमिका निभाई है।

संवेदनशीलता का स्पर्शः बुजुर्गों के लिए अलग सुविधा

अस्पताल ने सिर्फ तकनीक ही नहीं,बल्कि मानवीय पहलू पर भी ध्यान दिया है, 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों के लिए एनसीडी विंडो, लंबी कतारों से राहत,बीपी,शुगर और अन्य जांचों की निःशुल्क सुविधा, साथ ही मितानिन हेल्पडेस्क मरीजों को हर कदम पर मार्गदर्शन देता है–कहां जाना है, किससे मिलना है,किस जांच की जरूरत है–सब कुछ आसान बना दिया गया है।

आंखों के इलाज में आत्मनिर्भरताः गांव में ही मिलेगा 'नई रोशनी'

सोनहत अस्पताल ने अब आंखों के इलाज में भी बड़ी छलांग लगाई है, अत्याधुनिक जांच उपकरण पूरी तरह सुसज्जित आई ऑपरेशन थियेटर, अब क्षेत्र के बुजुर्गों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यहां स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण सर्जरी उपलब्ध है–वह भी सरकारी अस्पताल में।

तकनीक का नया युगः डिजिटल एक्स-रे और सोनोग्राफी

अस्पताल में तकनीकी सुविधाओं का विस्तार इस बदलाव की रीढ़ है, डिजिटल एक्स-रे यूनिट की पुनः शुरुआत,रेडिएशन सुरक्षा के मानकों के अनुरूप अलग कक्ष,आधुनिक सोनोग्राफी सुविधा,यह सुविधा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है,जिन्हें पहले जांच के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।

नवजात शिशुओं के लिए 'जीवन की सुरक्षा कवच'

एनबीएसयू (Newborn Stabilization Unit) को अत्याधुनिक बनाया गया है,कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए विशेष देखभाल, जीवनरक्षक उपकरणों से लैस वार्ड,साथ ही प्रसव कक्ष को संक्रमण मुक्त और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जिससे सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ जच्चा-बच्चा का लक्ष्य साकार हो रहा है।

जनता की नजर में 'हीरो' कौन?

स्थानीय लोग इस बदलाव का श्रेय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की इच्छाशक्ति,डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन और डॉ. बलवंत सिंह की जमीनी मेहनत को देते हैं।

सरकारी अस्पताल का बदला हुआ चेहरा

सोनहत का यह कायाकल्प सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जो कहती है सरकारी सिस्टम भी अगर चाहे,तो सबसे बेहतर बन सकता है,आज यह अस्पताल न केवल इलाज दे रहा है,बल्कि विश्वास,सम्मान और राहत भी दे रहा है,और यही किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता होती है।

स्वच्छता से सुकून तकः 'ग्रीन हॉस्पिटल' की नई पहचान

अब सोनहत अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण का प्रतीक बन गया है, चमचमाता परिसर, औषधीय और सजावटी पौधों से विकसित सुंदर गार्डन, स्वच्छ और आकर्षक ड्रेसिंग रूम, यहां अब दवाइयों की गंध से ज्यादा फूलों की खुशबू महसूस होती है—जो मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है।

'कायाकल्प अभियान' का असरः नियमों से बदली हकीकत

यह पूरा परिवर्तन शासन के 'कायाकल्प अभियान' का परिणाम है, जिसमें संक्रमण नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय मानक,वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन,दीवारों पर पेंटिंग और सूचना बोर्ड,रोजाना मॉनिटरिंग,बीएमओ डॉ. बलवंत सिंह स्वयं हर दिन निरीक्षण कर व्यवस्था को बनाए रखते हैं—यही इस सफलता का सबसे बड़ा राज है।

मंत्री के गृहग्राम में ही विकास ध्वस्त...करोड़ों की नहर एक महीने में दरक गई

गुणवत्ता नियंत्रण पर बड़ा सवाल

इस घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सामान्यतः ऐसे प्रोजेक्ट्स में तकनीकी स्वीकृति,साइट निरीक्षण,सामग्री परीक्षण,कार्य पूर्ण होने के बाद निरीक्षण जैसी प्रक्रियाएं अनिवार्य होती हैं,लेकिन यदि एक माह के भीतर ही निर्माण टूटने लगे,तो यह संकेत देता है कि या तो इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ या फिर कागजों में ही पूरा कर दिया गया।

मंत्री के गृहग्राम से उठे बड़े सवाल

यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि यह परियोजना मंत्री के गृहग्राम में ही बनाई गई थी,ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है यदि मंत्री के अपने क्षेत्र में ही निर्माण की यह स्थिति है,तो दूरदराज के क्षेत्रों में क्या हाल होगा? क्या निगरानी तंत्र वास्तव में काम कर रहा है? या फिर योजनाएं सिर्फ कागजों और उद्घाटन तक ही सीमित रह गई हैं?

विकास या दिखावा?

तामडाड़ जलाशय से जुड़ी यह नहर परियोजना किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति ने इसे सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है,यदि आरोप सही हैं और निर्माण में लापरवाही हुई है,तो यह सिर्फ एक परियोजना की विफलता नहीं,बल्कि पूरे विकास मॉडल पर सवाल है, अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों में दब जाएगा? सबसे बड़ा सवालः जब मंत्री के गृहग्राम में ही विकास कार्यों की यह स्थिति है, तो बाकी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कैसी होगी?

घटिया निर्माण का आरोप, किसानों को सिंचाई संकट का डर – जांच की मांग तेज

मंत्री के गृहग्राम में ही घटिया निर्माण!

करोड़ों की नहर लाइनिंग एक माह भी नहीं टिक पाई, जगह-जगह दरारें

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/रतनपुर,17 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी सिंचाई योजनाओं में शामिल तामडाड़ जलाशय से जुड़ी नहर लाइनिंग परियोजना अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। खास बात यह है कि यह परियोजना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के गृहग्राम रतनपुर में ही संचालित की गई थी, जहां विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आदर्श उदाहरण पेश किए जाने की उम्मीद थी। लेकिन वास्तविकता इसके उलट सामने आई है, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के अनुसार करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई नहर लाइनिंग एक माह भी नहीं टिक सकी और अब कई स्थानों पर दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। यह स्थिति न केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

क्या है पूरा मामला?

तामडाड़ जलाशय से निकलने वाली इस नहर का उद्देश्य आसपास के गांवों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना था, इसके लिए नहर की दीवारों और तल को मजबूत बनाने हेतु कंक्रीट लाइनिंग का कार्य कराया गया था, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके और अधिकतम खेतों तक पानी पहुंच सके, लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद नहर की सतह पर दरारें पड़ना शुरू हो गईं। कई स्थानों पर कंक्रीट की परत उखड़ने लगी है और किनारों पर टूट-फूट साफ नजर आ रही है, ग्रामीणों का आरोप है कि जहां उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग होना चाहिए था, वहां घटिया मिश्रण और मानकों की अनदेखी की गई, यही कारण है कि नहर की लाइनिंग इतनी जल्दी कमजोर पड़ गई।

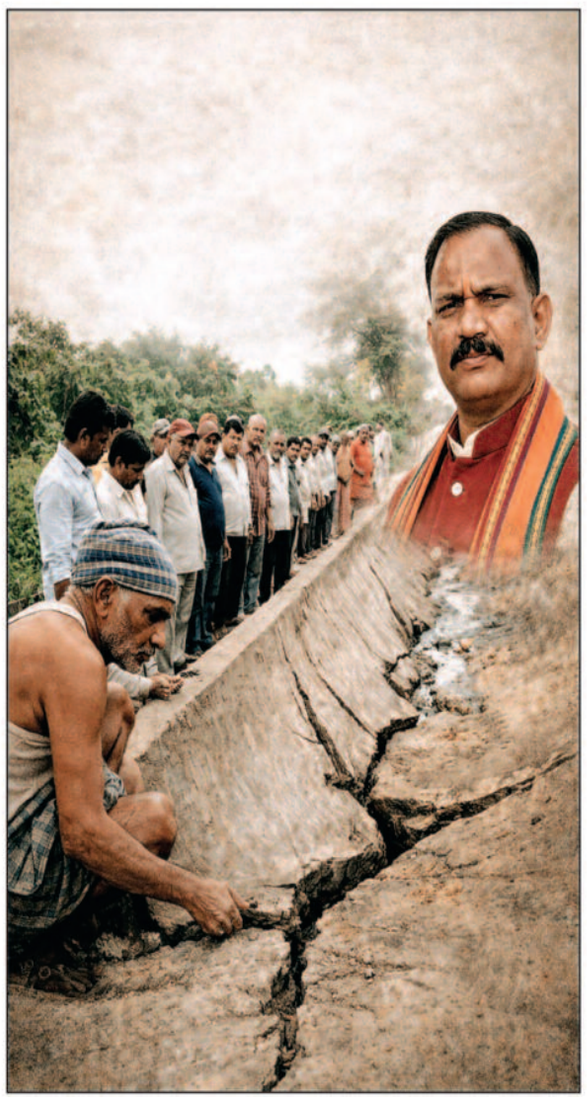

ग्रामीणों का आक्रोश और सवाल

स्थानीय निवासियों और किसानों में इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है,उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या निर्माण के दौरान किसी प्रकार का गुणवत्ता परीक्षण किया गया था? यदि किया गया था, तो फिर इतनी जल्दी दरारें क्यों आईं? एक किसान ने नाम न छापने की शर्त पर कहा हमने सोचा था कि अब खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन अब तो नहर ही टूटने लगी है,अगर यही हाल रहा तो पूरी योजना बेकार हो जाएगी।

किसानों के सामने संकट की आशंका

इस नहर का मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था,लेकिन लाइनिंग में आई दरारों के कारण अब पानी के रिसाव की आशंका बढ़ गई है,यदि नहर से पानी रिसने लगा तो खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचेगा,सिंचाई प्रभावित होगी,फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा,यह स्थिति किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है,खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई का यही मुख्य साधन है।

जांच की मांग तेज

मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है,उनका कहना है कि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच हो,उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका स्पष्ट की जाए,ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई,तो यह परियोजना भी अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी।

प्रशासन की चुप्पी ने बढ़ाए सवाल

इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक संबंधित विभाग या प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, प्रशासनिक चुप्पी के कारण लोगों में संदेह और गहरा रहा है,पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं,जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है,विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में प्रशासन को तुरंत सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जांच प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

CMYK

हम बचपन से ही अनिल कपूर के बड़े प्रशंसक रहे हैं : सुरेश त्रिवेणी

तुम्हारी सुलु और जलसा जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बना चुके बॉलीवुड निर्देशक सुरेश त्रिवेनी एक बार फिर अपनी नई फिल्म सुबेदार के जरिए दर्शकों के सामने एक भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। सुरेश त्रिवेणी का कहना है कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास और व्यक्तिगत महत्व रखती है। हाल ही में उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा, क्योंकि इसमें उन्हें अपने बचपन के पसंदीदा अभिनेता अनिल कपूर को निर्देशित करने का मौका मिला। सुरेश त्रिवेणी ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा कि वह झारखंड के रांची से आते हैं और बचपन से ही अनिल कपूर के बड़े प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब फिल्म तेजाब रिलीज हुई थी, तब 'मुन्ना' का किरदार लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था और वह भी उस दौर में अनिल कपूर के स्टाइल से काफी प्रभावित थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें आज भी याद है कि वह फिल्म लाडला से प्रेरित होकर ऑरेंज शर्ट पहनकर बड़े शौक से घूमते थे। उनके मुताबिक उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिलेगा। निर्देशक के अनुसार 'सुबेदार' उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा भी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह सिर्फ एक साधारण विचार था,लेकिन धीरे-धीरे यह एक गहरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में बदल गया। त्रिवेणी ने बताया कि इस फिल्म की कहानी भावना,विश्वास और उनके अपने अनुभवों से प्रेरित है। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने फिल्म का विचार साझा किया तो उन्हें तुरंत समर्थन मिला। सुरेश के अनुसार जैसे ही उन्होंने यह आइडिया निर्माता विक्रम के साथ साझा किया,उन्होंने तुरंत अनिल कपूर को फोन किया। निर्देशक के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अनिल कपूर ने बिना किसी झिझक के इस प्रोजेक्ट पर भरोसा जताया। फिल्म 'सुबेदार' 5 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है और इसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के बाद सुरेश त्रिवेणी अब अपनी अगली फिल्म मां बहन की तैयारी में जुट गए हैं, जिसे नेटफलीक्स के लिए बनाया जा रहा है।

श्रुति हासन के करियर की सबसे सफल फिल्म 'श्रीमंथुडू'
रेटिंग में नंबर 1 और कमाई में ब्लॉकबस्टर

अभिनेत्री और गायिका श्रुति हासन 39 साल की हो गई हैं। कमल हासन की विरासत को अपनी मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ाने वाली श्रुति ने न केवल दक्षिण भारतीय फिल्मों में, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिल्म के बारे में,जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही,बल्कि IMDb पर भी सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ दर्शकों और समीक्षकों की पहली पसंद बनी हुई है।

'श्रीमंथुडू' ने श्रुति हासन को दिलाई करियर की सबसे बड़ी कामयाबी

श्रुति ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन साल 2015 में आई 'श्रीमंथुडू' ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचा दिया। कोरतल्ला शिवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रुति ने न केवल अपनी खूबसूरती,बल्कि अपने संजीदा अभिनय से भी लोगों को प्रभावित किया। इस फिल्म को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है, जो किसी भी कमर्शियल मसाला फिल्म के लिए बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। इतनी रेटिंग श्रुति की किसी भी फिल्म को नहीं मिली है।

'चारुसीला' बनकर छाई श्रुति

फिल्म में श्रुति द्वारा निभाए गए 'चारुसीला' के किरदार को काफी सराहा गया। समीक्षकों ने महेश बाबू के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फिल्म की जान बताया। गांव को गोद लेने और अपनी जड़ों से जुड़ने की इस भावनात्मक एक्शन ड्रामा फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। इसने श्रुति को वो मुकाम दिया,जहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाई,जो स्वतंत्र, शिक्षित और मजबूत विचारों वाली है।

60 करोड़ के बजट में कमाए? 200 करोड़

'श्रीमंथुडू' 2015 की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक थी। इसने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। उस समय के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा था। जिस दौर में 'बाहुबली : द बिगिनिंग' ने पूरे भारत में तहलका मचा रखा था,उसी साल रिलीज हुई 'श्रीमंथुडू' ने अपना अलग मुकाम बनाया। ये

'बाहुबली' के बाद तेलुगू सिनेमा के इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म का बजट 60 करोड़ था।

श्रुति की आने? वाली फिल्में

नंदी पुरस्कार से लेकर फिल्मफेयर पुरस्कार तक जीतने वाली इस फिल्म ने श्रुति की फिल्मावली में चार चांद लगा दिए थे। श्रुति की आने वाली फिल्मों की बात करें तो प्रभास के साथ 'सालार' की सफलता के बाद श्रुति अब इसके दूसरे भाग 'सालारः पार्ट 2 - शौर्यांग पर्व' में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएंगी। उनके पास थ्रिलर फिल्म 'ट्रेन' भी है ।

पूनम ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में रखा था मॉडलिंग की दुनिया में कदम

अपने करियर के दौरान चर्चित मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने कई बार विवादों के कारण सुर्खियां बटोरीं और एक समय ऐसा भी आया जब उनके द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया था। पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में पूरी की और महज 18 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अपने बोल्ड फोटोशूट्स के कारण वह जल्दी ही चर्चा में आ गई और सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। वर्ष 2010 में उन्होंने ग्लैडरैग्स मैनहंट और मेगा मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया,जहां वह टॉप 9 प्रतिभागियों में शामिल रहीं। इसके बाद उन्होंने कई कैलेंडर और फोटोशूट्स में काम किया,जिनमें 2012 का किंगफिशर कैलेंडर विशेष रूप से चर्चा में रहा। साल 2011 में पूनम पांडे अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई,जब उन्होंने कहा कि यदि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतती है तो वह न्यूड हो जाएंगी।

इस बयान ने उन्हें रातोंरात चर्चा का विषय बना दिया। विवादों के बीच उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा और 2013 में फिल्म नशा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक स्कूल टीचर की भूमिका निभाई, जिसमें कई बोल्ड दृश्य शामिल थे। फिल्म का पोस्टर रिलीज होने के बाद कुछ जगहों पर

इसका विरोध भी हुआ और प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर जलाकर नाराजगी जताई। बाद में उन्होंने 'मालिनी एंड कंपनी', 'द जर्नी ऑफ कर्मा', 'लव इज पॉइजन' और 'आ गया हीरो' जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों के अलावा पूनम ने टीवी और रियलिटी शो में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने फीयर फेक्टरःखतरों के खिलाडी के चौथे सीजन और लॉकअप जैसे चर्चित रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके साथ ही वह 'टोटल नादानियां' और 'प्यार मोहब्बत श्श्श' जैसे कार्यक्रमों में भी नजर आईं। साल 2017 में पूनम पांडे ने अपने नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया,जिसमें उनका बोल्ड और एडल्ट कंटेंट उपलब्ध था। हालांकि यह ऐप ज्यादा समय तक नहीं चल सका और गूगल ने अपनी नीतियों का हवाला देते हुए इसे प्ले स्टोर से केवल एक घंटे के भीतर हटा दिया। इस घटना ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया। निजी जीवन की बात करें तो पूनम पांडे ने 2020 में अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड सेम बॉम्बे से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पति पर धमकी और मारपीट का आरोप लगाया,जिसके बाद गोवा पुलिस ने सैम को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई। इसके बावजूद पूनम पांडे का नाम विवादों से जुड़ा रहा और वह लगातार चर्चा में बनी रहीं। साल 2024 में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर लोगों को चौंका दिया था। बाद में उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना था। हालांकि इस कदम के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा।

खेल समाचार

लैंगर-मूडी ने मैदानकर्मियों को भेंट की एलएसजी की जर्सी

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। आगामी सीजन की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के हेड कोच जस्टिन लैंगर और क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी ने मंगलवार को अपने घरेलू मैदान भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैदानकर्मियों को जर्सी भेंट की। एलएसजी की टीम आईपीएल 2026 में अपने अभियान का आगाज एक अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर करेगी। इसके बाद टीम अपना अगला मुकाबला 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। आईपीएल 2026 के पहले चरण के शेड्यूल के मुताबिक,लखनऊ सुपर जायंट्स को 4 मैच खेलने हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी में एलएसजी 9 अप्रैल को ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। वहीं,12 अप्रैल को टीम का सामना घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस से होगा। लखनऊ टीम की तैयारियां जोरों पर हैं। कई खिलाड़ी टीम के कैंप से जुड़ चुके हैं और जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी के भी जल्द कैंप से जुड़ने की उम्मीद है। लैंगर और मूडी के मैदानकर्मियों को भेंट की गई नई जर्सी की तस्वीरें शेयर करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा,'हमारे मैदानकर्मियों के लिए, सीधे हमारे दिल से। 'लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्रेनिंग सेशन के दौरान बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी अब्दुल समद और हिम्मत सिंह के साथ-साथ ऑलराउंडर आयुष बदोनी,शाहबाज अहमद और अर्शिन कुलकर्णी ने नेट्स में प्रभावित किया। अर्जुन तेंदुलकर,मयंक यादव,आवेश खान के पेस अटैक ने अपनी रफ्तार और शानदार लाइन एंड लेंथ के लिए कोचिंग स्टाफ से तारीफ बटोरी।

चेल्सी पर 92 करोड़ का जुर्माना...ट्रांसफर बैन भी लगा,ईडन हजार्ड और विलियन के लिए गुप्त भुगतान किए गए,क्लब ने खुद कबूली अपनी गलती

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। प्रीमियर लीग ने चेल्सी फुटबॉल क्लब पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन के मामले में 92(10 मिलियन पाउंड) करोड़ का जुर्माना लगाया है। क्लब पर एक साल का ट्रांसफर बैन लगाया गया है, लेकिन इसे दो साल के लिए टाल दिया गया है। यह कार्रवाई 2011 से 2018 के बीच किए गए गुप्त भुगतानों को लेकर की गई है। क्लब ने ईडन हजार्ड,विलियन और डेविड लुइज जैसे बड़े खिलाड़ियों को साइन करने के लिए अनरजिस्टर्ड एजेंटों को करोड़ों रुपए दिए थे। यह पूरी गड़बड़ी उस समय की है जब क्लब के मालिक रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच थे। साल 2022 में जब 'ब्लूको' ग्रुप ने क्लब को खरीदा, तो उन्हें अकाउंट्स की जांच के दौरान इन गुप्त भुगतानों का पता चला। नए मैनेजमेंट ने खुद आगे बढ़कर प्रीमियर लीग को इन उल्लंघनों की जानकारी दी। जांच में सामने आया कि क्लब से जुड़े तीसरे पक्ष के जरिए खिलाड़ियों, अनरजिस्टर्ड एजेंटों और अन्य लोगों को गुप्त भुगतान किए गए थे। इन भुगतानों की जानकारी उस समय फुटबॉल अथॉरिटी को नहीं दी गई थी,जो कि नियमों के खिलाफ है। प्रीमियर लीग के अनुसार ये भुगतान चेल्सी के हित में किए गए थे और इन्हें क्लब के खर्च के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। क्लब ने यह भी माना कि इन भुगतानों को छिपाना और सही जानकारी न देना नियमों का उल्लंघन है। हालांकि जांच के बाद यह साफ हुआ कि अगर इन भुगतानों को सही तरीके से शामिल भी किया जाता,तब भी चेल्सी नियमों का उल्लंघन नहीं करती। अगर क्लब खुद इसकी जानकारी नहीं देता,तो उन पर और भी सख्त कार्रवाई हो सकती थी और उनके प्वॉइंट्स भी काटे जा सकते थे। जिन खिलाड़ियों के ट्रांसफर पर विवाद है,वे चेल्सी के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 68 रन से हराया

फर्ग्यूसन-सीयर्स की घातक गेंदबाजी, लिंडे ने 275 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। न्यूजीलैंड ने हेमिल्टन में मंगलवार को साउथ अफ्रीका को 68 रनों से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज को दो मैच के बाद 1-1 से बराबर कर ली। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने ड्वेन कॉनवे की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए। साउथ अफ्रीका पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स ने कहर बरपाया। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। साउथ अफ्रीका 15.3 ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 275 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तीसरा मैच शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड की पारी : न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने 49 गेंद पर 60 रन बनाए। जोश क्लार्कसन ने 9 गेंद पर नाबाद 26 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 14 गेंद पर 20 और निक केली ने 12 गेंद पर 21 रन बनाए। कोल मैककोन्ची ने 12 गेंद पर नाबाद 18 रन बनाए। जेम्स नीशम में 11 गेंद पर 8 रन बनाए। टिम रॉबिनसन ने 1 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर ने 2 विकेट लिए। जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, ओटनिल बार्टमैन और गेराल्ड कोएत्जी ने 1-1 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका की पारी : साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 12 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। रुबिन हरमन ने 12 गेंद पर 19 रन बनाए। वियान मुल्डर ने 16, जेसन स्मिथ ने 12 और डियान फॉरेस्टर ने 10 रन बनाए। जेराल्ड कोएत्जी ने 2 और टोनी डी जॉर्जी ने 1 रन बनाए। केशव महाराज और नकोबानी मोकोएना खाता नहीं खोल पाए। ओटनिल बार्टमैन बगैर खाता नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स ने 3-3 विकेट लिए। मिचेल सैंटनर ने 2 विकेट लिए। कोल मैककोन्ची और जेम्स नीशम ने 1-1 विकेट लिए।

मुम्बई के लिए कठिन होगा सभी विदेशी खिलाड़ियों को अवसर देना : चोपड़ा

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि इस माह के अंत में शुरु हो रहे आईपीएल मुकाबलों में मुम्बई इंडियंस के लिए विदेशी खिलाड़ियों को अवसर देना आसान नहीं रहेगा। आकाश के अनुसार मुम्बई टीम के पास कई विदेशी खिलाड़ी हैं पर सभी को अवसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके पास अपने देश के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अलावा स्पिनर राहुल चाहर भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकता है। बुमराह के होने से तय है कि उनके चारों ओवर काफी अच्छे रहेंगे। बुमराह ने आईपीएल 2025 में कुल 12 मैच खेले, जिसमें 17.56 की औसत के साथ 18 विकेट लिए थे। मुम्ब ई अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई में अपने घरेलू मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ करेगी। आईपीएल के पिछले सत्र में टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची थी पर यहां उसे पंजाब किंग्स ने हरा दिया था। चोपड़ा ने कहा, बुमराह पर अपने आप दबाव आ जाता है। वह एक शीर्ष स्तर के गेंदबाज हैं और उन्हें उसे बनाये रखना होता है। वह हर मैच में प्रभाव डालते हैं। एक विकेट की गारंटी देते हैं और विरोधी टीम को रोकते हैं।

वॉन ने विराट और बुमराह को आईपीएल इतिहास का बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज करार दिया

मुम्बई,17 मार्च 2026। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि आईपीएल में सबसे महान बल्लेबाजों की बात की जाये तो वह रॉयल चैलेंर्स बेंगलुरु के विराट कोहली को नंबर एक स्थान देते हैं, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नंबर एक स्थान पर रखा है। वॉन ने कहा कि इस लीग में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी रहे हैं पर विराट सबसे अलग हैं। उनके खेल में जिस प्रकार की निरंतरता रही है कोई उसके करीब नहीं है। इस पूर्व कप्तान ने कहा कि क्रिस गेल, सुरेश रैना , रोहित शर्मा और जोस बटलर जैसे बल्लेबाजों ने भी इस लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है पर विराट की बात अलग रही है। वॉन ने कहा, कई अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इसमें क्रिस गेल, सुरेश रैना के अलावा रोहित शर्मा और जोस बटलर हैं पर अगर एक नाम तय करना हो तो वह विराट ही होंगे। वह कई वर्षों से स्टार खिलाड़ी रहे हैं और अभी भी शानदार खेल रहे हैं।वहीं वॉन ने तेज गेंदबाज जसपीत बुमराह को लीग का नंबर एक गेंदबाज बताया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान और श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसित मलिंग भी काफी अच्छे रहे हैं पर बुमराह सबसे अलग हैं।

वॉन के अनुसा दबाव के क्षणों में बुमराह की सटीक गेंदबाजी और डेथ ओवरों में उनकी क्षमता उन्हें इस लीक का शीर्ष गेंदबाज बनाती है। इसके अलावा उन्होंने मुम्बई इंडियंस को लीग की सबसे सफल टीम करार दिया। वॉन के अनुसार मुम्बई का पांच खिताबी जीत को सफर सफल रोमांचक रहा है। उनके अनुसार ये टीम हालात देखकर बदलते अंदाज में खेलती है।

आईपीएल 2026 : राजस्थान रॉयल्स से जुड़े वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल

नई दिल्ली,17 मार्च 2026। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़ गए हैं। राजस्थान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स अपने अभियान का आगाज 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करेगी। पिछले सीजन राजस्थान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। टीम 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी थी। राजस्थान ने 9वें स्थान पर

रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया था। आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान ने रियान पराग को कप्तान बनाया है। राजस्थान की ओर से इस बार रवींद्र जडेजा और सैम करन खेलते हुए दिखाई दे देंगे। टीम ने जडेजा और करन को संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड किया है। वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन आईपीएल 2025 में शानदार रहा था। 14 वर्षीय बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7 मुकाबलों में 206 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए थे। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था। वह आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। राजस्थान रॉयल्स के लिए भले ही पिछला सीजन खराब रहा था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था।

यशस्वी ने 14 मुकाबलों में 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 559 रन बनाए थे। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 अर्धशतक लगाए थे। आईपीएल 2026 में राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में यशस्वी के ऊपर इस सीजन बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं, इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में रियान पराग की कप्तानी का भी टेस्ट होगा।

हेमिल्टन में दक्षिण अफ्रीका का धमाका...न्यूजीलैंड को 18 रन से हराकर सीरीज में की 1-1 से बराबरी

हैमिल्टन,17 मार्च 2026। साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 18 रनों से हराया। हैमिल्टन के सेडन पार्क में साउथ अफ्रीका से मिले 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में जीत के साथ ही सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जॉर्जिया प्लिमर महज एक रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज इसाबेला गेज भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और 6 रन बनाकर आउट हुईं। 31 के स्कोर पर 2 विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीका की लड़खड़ाती हुई पारी को कप्तान अमेलिया केर और सोफी डिवाइन ने संभाला। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। हालांकि, डिवाइन अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहीं और 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। अमेलिया केर ने 18 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। इजी शार्प ने 21 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि जेस केर ने 10 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी में अयाबोंगा खाका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले। वहीं, नॉनकुलुलको म्लाबा ने 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 177 रन लगाए। टीम की ओर से ताजमिन ब्रिट्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 53 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 33 गेंदों में 41 रन बनाए। पहले विकेट के लिए ब्रिट्स और सुने लुस ने मिलकर 6.6 ओवर में 62 रन जोड़े और साउथ अफ्रीका को बढ़िया शुरुआत दी। लुस ने 21 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाए। इसके बाद कप्तान वोल्वार्ट और ब्रिट्स ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े। ब्रिट्स ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए। अंत के ओवरों में कायला रेनके ने सिर्फ 9 गेंदों में 311 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 28 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में अमेलिया केर और जेस केर ने दो-दो विकेट चटकाए।

विधानसभा में 'जी राम जी' पर हंगामा...भूपेश ने मनरेगा को बताया बेहतर

ऐसा कोई सगा नहीं,जिसे कांग्रेसियों ने ठगा नहीं : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन सदन में अवैध प्लॉटिंग और 'जी राम जी' के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा को बेहतर बताया। जवाब में सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने कहा सदन विपक्ष की राजनीति का अड्डा नहीं है। जिसके बाद विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सीएम ने कांग्रेस के 5 सालों के शासन को कुशासन करार देते हुए कहा, ऐसा कोई सगा नहीं,जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। दिलचस्प बात यह रही कि जब मुख्यमंत्री सदन में कांग्रेस सरकार के कारनामों की गिनती करा रहे थे,तब विपक्षी विधायक सदन से नदारद थे। कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से पूछा- 2024 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक कितनी शिकायतें मिलीं? उन्होंने अवैध प्लाटिंग को लेकर खसरों की जांच और कार्रवाई की जानकारी मांगी।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा...

धमतरी में 3 शिकायतों की जानकारी मिली है। कांकेर में 5 शिकायत मिली,कुल 175 खसरा में 8 की जांच हुई। जांच और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब 3 पटवारी का इंक्रीमेंट रोका गया है। कई अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस दिया गया,अवैध प्लाटिंग को रोकने पर पूरा जोर है।

गौठानों में गौमाता की दुर्दशा देख खून के आंसू आते थे

सीएम साय ने नरवा,गरवा,घुरुवा,बारी योजना पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि गौठानों के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई फूंक दी गई। सीएम ने भावुक होते हुए कहा...जब हम गौठानों में गायों की दुर्दशा देखते थे,तो हमारे खून के आंसू निकल आते थे।

शराब घोटाला और दो काउंटर का सच

सदन में शराब घोटाले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में शराब के दो काउंटर चलते थे एक कांग्रेस का एटीएम था और दूसरे काउंटर का पैसा सीधे उनकी जेब में जाता था। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि उनकी सरकार में आबकारी राजस्व 11 हजार करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस के समय यह सिर्फ 5 हजार 100 करोड़ था।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ये सवाल प्रत्येक सत्र में आता है। प्रदेश में कितने अवैध कॉलोनी बनी। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है।

नर्सरी और वृक्षारोपण को लेकर सवाल

- इसके बाद कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने महासमुंद वनमंडल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के जंगलबेड़ा गांव में नर्सरी और वृक्षारोपण को लेकर सवाल पूछा। चातुरी नंद ने मूल प्रश्न बदलने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल- मामला बेहद गंभीर है,मूल प्रश्न बदला गया है, ऐसे में जांच कर दोषी विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
- वन मंत्री केदार कश्यप-2025 को लेकर प्रश्न पूछा गया है,जिसका उत्तर हम दे रहे हैं।
- विधायक चातुरी नंद-मेरा मूल प्रश्न 2025 को लेकर था ही नहीं।
- आसंदी से सभापति ने कहा...प्रश्न अनिश्चितकाल के संदर्भ में था,क्योंकि अवधि उल्लेखित नहीं थी,इसलिए अवधि तय की गई,वरना प्रश्न नहीं लिया जा सकता था।

मंत्री टंक राम वर्मा- अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कार्रवाई करने का। तीनों पटवारी के वेतन वृद्धि को रोका गया है। 67 लोगों को नोटिस दिया गया है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर - आपने कहा अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई नहीं करने का कारण एसआईआर को बताया, लेकिन ये कॉलोनी कब बनी।

भारतमाला मुआवजा घोटाला...

निलंबित एसडीएम गिरफ्तार

24 करोड़ की संपत्ति अटैच,अधिग्रहित जमीन को दोबारा अधिग्रहण दिखाकर मुआवजा बांटा था...

रायपुर,17 मार्च 2026। भारत माला परियोजना के मुआवजा घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 30 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने निर्भय की 23.35 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया है। जांच में पाया गया कि निभर्य साहू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर घोटाले को अंजाम दिया था। इस दौरान अभनपुर तहसील के ग्राम नायकबांधा,उगेटरा,उरला, भेलवाडीह और टोकरो की प्रभावित भूमि को बैकडेट में कई खंडों में विभाजित किया। इसके माध्यम से वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, पहले से अधिग्रहित भूमि को भी दोबारा अधिग्रहण दिखाकर मुआवजा वितरित किया गया, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ।

लंबे समय से फरार चल रहा था...

बताया जा रहा है कि आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुकी थी और उसके खिलाफ विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। इसके बावजूद निलंबित एसडीएम लगातार लंबे समय से फरार चल रहा था।

प्रवर्तन निदेशालय ने 23 करोड़ की प्रॉपर्टी की अटैच : इस घाटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23.35 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय की रायपुर जोनल ऑफिस की जांच में सामने आया है कि,रायपुर-विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। इस मामले की शुरुआती जांच ईओडब्ल्यू /एसीबीकी तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी।

फर्जी दस्तावेजों से बढ़ाया मुआवजा

जांच में खुलासा हुआ है कि, जमीन दलालों, निजी व्यक्तियों और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर साजिश रची। जमीनों को फर्जी तरीके से छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक रकम हासिल की गई।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा दखल...नदी संरक्षण में अफसरों की जगह विशेषज्ञों को कमान

बिलासपुर,17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ की नदियों के संरक्षण को लेकर अब सिर्फ बैठकों और सरकारी फाइलों से काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि नदियों को बचाने के लिए ज़मीनी समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है। इसी सोच के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई कमेटी में बड़ा बदलाव करते हुए प्रशासनिक सचिवों की जगह विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि अब तक नदी संरक्षण योजनाएं कागज़ों तक सीमित रहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह,प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्जीवन के लिए केवल प्रशासनिक अनुभव नहीं, बल्कि हाइड्रोलॉजी,पर्यावरण और भूगोल के विशेषज्ञों की भूमिका अहम होगी। नई रणनीति में नदियों को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी शामिल है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में राज्य की प्रमुख नदियों–अरपा, महानदी, शिवनाथ,हसदेव, तांदुला, पैरी, मांड,केलो,सोन, तिपान और लीलगर–को शामिल किया गया है,जिनके लिए वैज्ञानिक सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस योजना को गति देने के लिए सरकार सिर्फ एक बजट पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि छ्रस्न्न, मनरेगा और 15 वें वित्त आयोग जैसे अलग-अलग स्रोतों से फंड जुटाए जाएंगे।

अम्बेडकर अस्पताल में 11 साल के बच्चे के दिल से चिपका दुर्लभ कैंसर निकाला,बना विश्व कीर्तिमान

रायपुर,17 मार्च 2026। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉक्टरों ने 11 वर्ष के बच्चे के हृदय से चिपके दुर्लभ स्टेज-3 इनवेसिव थायमिक कैंसर का सफल ऑपरेशन कर विश्व स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मेडिकल जर्नल के अनुसार अब तक ऐसा सबसे कम उम्र का मरीज 12 वर्ष का दर्ज था, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस सफल केस ने अब नया रिकॉर्ड बना दिया है। विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू और उनकी टीम ने बताया कि यह ट्यूमर (इनवेसिव थाइमोमा) आमतौर पर 40 से 60 वर्ष के बुजुर्गों में होता है। बच्चे के मामले में यह ट्यूमर हार्ट, महाधमनी और फेफड़ों से बुरी तरह चिपका हुआ था। इसे निकालने के लिए 'ड्यूल एप्रोच तकनीक' (स्टर्नोटॉमी और थोरेक्टोमी) का इस्तेमाल किया गया। लगभग 4 घंटे चली इस जटिल सर्जरी में हार्ट-लंग मशीन का सहारा लिया गया। ट्यूमर का आकार 12म8 सेंटीमीटर और वजन करीब 400 ग्राम था। सर्जरी के बाद बच्चे को 25 साइकिल रेडिएशन थेरेपी दी गई,जिसके बाद वह अब पूरी तरह स्वस्थ है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की वैश्विक स्तर पर मजबूती को दर्शाती है। चांपा निवासी इस बच्चे को कई बड़े निजी अस्पतालों ने जोखिम के कारण मना कर दिया था,लेकिन राजधानी के सरकारी अस्पताल में मुफ्त और सफल इलाज मिलने से अब वह बच्चा दोबारा स्कूल जाकर सामान्य जीवन जी रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ के मरीजों को जटिल ऑपरेशनों के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है।

आरक्षक ट्रेन से कटा,रेलवे पटरी पार करने के दौरान हुई घटना में मौत

रायगढ़,17 मार्च 2026। जिले के पुलिस बल में पदस्थ एक आरक्षक की हादसे में मौत की खबर से महकमें में हड़कंप मच गया है। मृत आरक्षक का नाम सुजीत मिंज बताया जा रहा है। आरक्षक सुजीत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ था। बताया जा रहा है कि,रेलवे पटरी पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हादसा किन वजहों से हुआ इसकी जाँच की जा रही है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेबल के मौत से उनके साथियों में शोक की लहार दौड़ गई है।

मनरेगा-सिलेंडर की कीमतों पर कांग्रेस ने विधानसभा घेरा....

2028 में छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार : भूपेश बघेल

रायपुर,17 मार्च 2026। मनरेगा का नाम बदलने, सिलेंडर की बढ़ी कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाली से गैस चूल्हा जोड़कर चाय बनाकर विरोध जताया। बैरिकेड्स तोड़कर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। पुलिस प्रशासन ने टीन का शेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हम डेढ़ गुना मनरेगा की राशि देंगे। यह प्रदर्शन राज्य में विपक्ष के रूप में कांग्रेस की नई रणनीति और सक्रियता को दर्शाता है। मनरेगा, बिजली दरों में वृद्धि और कानून व्यवस्था जैसे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ना तय है।

अफीम की खेती और महंगाई पर सरकार को घेरा

कांग्रेस का यह 'विधानसभा घेराव' मुख्य रूप से 'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत आयोजित किया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध अफीम की खेती फल-फूल रही है और सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम,बिजली कटौती और धान खरीदी में हुई कथित वादाखिलाफी को लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने रायपुर के मरीन ड्राइव से लेकर विधानसभा मार्ग तक कड़े बंदोबस्त किए और कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए। प्रदर्शन स्थल को लेकर प्रशासन और कांग्रेस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सरकार और गरीबों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है,लेकिन वर्तमान सरकार इसे बढ़ा रही है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा...हम गरीबों के लिए जिएंगे और उन्हीं के लिए मरेंगे,लेकिन उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज को बैरिकैट्स पर चढ़ाया। बैज ने कहा सरकार ने टिन का शेड लगाकर हमें आगे जाने से रोक दिया। लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं तोड़ना चाहते। इसलिए हमारा विधानसभा घेराव सपंन्न हुआ। सचिन पायलट बोले ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत आ गया है। अगर बाजपेयी जी की सरकार होती को ऐसा कभी नहीं होता।

मंदिर-मस्जिद की आड़ में अब वोट नहीं मिलेगा,रायपुर में गरजे सचिन पायलट

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधानसभा घेराव में शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा को यह गलतफहमी है कि वह मंदिर-मस्जिद की आड़ लेकर जनता का वोट पा लेगी, जबकि जनता अब उनके अत्याचार और शोषण को समझ चुकी है। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा का 90 प्रतिशत पैसा केंद्र से आता था, लेकिन अब निर्णयों का केंद्रीकरण कर पूरी योजना को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने विदेशी नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के निर्णय बाहरी ताकतों के दबाव में दिख रहे हैं, चाहे वह रूस से तेल लेने का मामला हो या युद्ध पर विराम लगाने की बात। पायलट ने भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रही अवैध अफीम की खेती को उजागर कर सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में एलपीजी की भारी किल्लत और कालाबाजारी हो रही है,लेकिन सरकार के आंख-कान बंद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरना और प्रदर्शन से भले ही इमारतें न टूटें, लेकिन जनता की जागृत शक्ति किसी भी अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है।

भूपेश ने कहा...नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि देश और प्रदेश में आज गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है और इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीन जगहों पर अफीम की खेती पकड़ी गई है और यदि इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में यह 100 गुना बढ़ जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए बिजली दरों में बढ़ोतरी और धान खरीदी में वादाखिलाफी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रमुख मुद्दे: मनरेगा योजना में कटौती, अफीम की अवैध खेती, गैस और बिजली के बढ़ते दाम।

भिलाई में बच्चों के विवाद के बाद पथराव....

सीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल,भारी बल तैनात

दुर्ग-भिलाई,17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर भिलाई में दो पक्षों के बीच उपजा मामूली विवाद एक बड़ी हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनकर मोहल्ले में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। विवाद की शुरुआत खेल-खेल में बच्चों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के बड़े लोग भी आमने-सामने आ गए। जुबानी जंग ने जल्द ही मारपीट और पथराव का रूप ले लिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि दोनों गुटों की ओर से जमकर पत्थर चले,जिससे न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा,बल्कि कानून व्यवस्था को भी गंभीर चुनौती मिली। हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुँची, लेकिन उन्मादी भीड़ को शांत करना आसान नहीं था। उपद्रवियों द्वारा किए जा रहे पथराव की चपेट में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी आ गए। जानकारी के मुताबिक,

इस पत्थरबाजी में छावनी सीएसपी समेत कुल 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थिति को बिगड़ता देख जिले के आला अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। दुर्ग, भिलाई और छावनी के सीएसपी के साथ एडिशनल एसपी (सिटी और ग्रामीण) भारी पुलिस बल के साथ देर रात तक मौके पर डटे रहे। कई थाना प्रभारियों की तैनाती के बाद किसी तरह स्थिति पर काबू पाया जा सका। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में बच्चों का विवाद सामने आया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और एक पक्ष के आरोपों ने मामले में नया मोड़ दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा के तार एक पुराने 'लव अफेयर' और रंजिश से जुड़े हो सकते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि कुछ समय पहले मोहल्ले का एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर भाग गया था। बाद में युवक को जेल भेज दिया गया और युवती को परिजनों के सुपुर्द किया गया। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष घात लगाए बैठे थे और बच्चों का विवाद महज एक तात्कालिक कारण बना। पुलिस अब इस प्रेम प्रसंग वाले एंगल की भी गहनता से जांच कर रही है।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह

रायपुर,17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और संवेदनशील शासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह कराकर राज्य ने सामाजिक एकता और अंत्योदय की भावना को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया है। 10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में कुल 6,412 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि बाकी जोड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सभी विवाह पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुए, जिससे यह आयोजन एक विशाल सामाजिक उत्सव के रूप में सामने आया।

हाईकोर्ट ने एसईसीएल के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका की खारिज,कहा...कंपनी को शर्तों की व्याख्या का अंतिम अधिकार

बिलासपुर,17 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसईसीएल के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि टेंडर की शर्तों की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उस विभाग या कंपनी के पास है जिसने टेंडर जारी किया है। एसईसीएल ने कोरबा क्षेत्र की बगदेवा भूमिगत खदान के लिए नवनिर्मित स्वदेशी कंटीन्युअस माइनर मशीन के लिए ट्रायल टेंडर जारी किया था। रायपुर की कंपनी मोश वरया ने इसके लिए बोली लगाई और सैंडविक मॉडल एमसी-350 मशीन का प्रस्ताव दिया। कंपनी का दावा था कि यह मशीन पुणे में बनी है और इसमें 57।23% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे नवनिर्मित माना जाए। एसईसीएल की टेक्निकल कमेटी ने कंपनी की बोली यह कहते हुए खारिज कर दी कि सैंडविक का यही मॉडल पहले से ही हल्दीपला खदान में काम कर रहा है।

जबकि टेंडर की स्पष्ट शर्त थी कि मशीन नवनिर्मित होनी चाहिए और भारत की किसी भी खदान में पहले उपयोग नहीं की गई होनी चाहिए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टेंडर जारी करने वाली अथॉरिटी प्रोजेक्ट की जरूरतों को समझने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होती है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)